सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

"आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए सकारात्मक सोचें और खुश रहें...!!"
अज्ञात...

वर्ष-01 अंक-141 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, बुधवार 10 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 7 बड़े फैसले : पावर कंपनी का आईपीओ लाने की मंजूरी

किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार, कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप मंजूर, 4 शहरों में दौड़ेंगी 240 ई-बसें

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सात अहम फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को आईपीओ के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई। खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी मिली।

धान के बदले दूसरी फसल पर 15 हजार प्रति एकड़

कैबिनेट ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 2026-27 में चना वितरण जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नेकडेक्स-ई-मार्केट के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से अधिकतम 0 .25 प्रतिशत सर्विस चार्ज पर चना खरीदेगा। अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह की अवधि बढ़ाई गई।
2. योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाया जाएगा।
3. नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर मिल रही मुद्रांक शुल्क छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई गई।
4. छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी। खनिज परिवहन वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाया गया।

पावर कंपनी का आएगा IPO

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई। इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है।

240 ई-बसों के संचालन को मंजूरी

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हुआ। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति दी।

"बासमती बाबा" दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार, पुलिस ने की कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / बागबाहरा

चावल के दानों से भविष्यवाणी करने के दावे के लिए क्षेत्र में चर्चित स्वयंभू भविष्यवक्ता नरेंद्र शास्त्री उर्फ "बासमती बाबा" को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना बागबाहरा में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(j), 376(2)(n) एवं 376(2)(m) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।

6 जून को मिली थी शिकायत

पुलिस के मुताबिक 06 जून 2026 को पीड़िता ने थाना बागबाहरा में लिखित आवेदन देकर आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद विधिसम्मत कार्रवाई शुरू की गई और तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। साक्ष्य संकलित करने के बाद 09 जून 2026 को नरेंद्र शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया।

अनुयायियों में थी मान्यता

नरेंद्र शास्त्री "बासमती बाबा" के नाम से क्षेत्र में जाने जाते थे। अनुयायियों के बीच मान्यता थी कि

वे चावल के दानों से नौकरी, विवाह, राजनीतिक सफलता और व्यक्तिगत समस्याओं पर भविष्यवाणी करते हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाते थे।

पुलिस बोली: जांच निष्पक्ष होगी

गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में चर्चाएं तेज हैं। कुछ लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। साक्ष्यों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने पर ही आएगा।

फिलहाल आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पीएम मोदी बने सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित पीएम, पं. नेहरू का रिकॉर्ड टूटा

26 मई 2014 से अब तक 4,399 दिन पूरे, 9 जून 2024 को तीसरी बार ली थी शपथ

नई दृष्टिबिंदु / नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है।

4,399 दिन का कार्यकाल पूरा

पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 9 जून 2026 तक उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए हैं। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार 4,398 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। इस तरह मोदी का कार्यकाल नेहरू से एक दिन अधिक हो गया है।

तीसरी बार 9 जून 2024 को ली शपथ

नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को एनडीए के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 9 जून 2026 को उनके सत्ता में 12 साल भी पूरे हो गए। 2014 में भाजपा को लोकसभा में पहली बार पूर्ण बहुमत दिलाने के बाद से वे लगातार प्रधानमंत्री पद पर हैं।

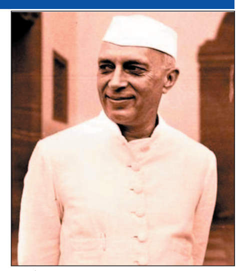

नेहरू बिना चुनाव पीएम बने थे

पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में बिना किसी चुनाव के प्रधानमंत्री बने थे। लोकतांत्रिक रूप से वे 13 मई 1952 को प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 4,077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहीं थीं।

अवैध डीजल-पेट्रोल का जखीरा बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

कबीर नगर पुलिस ने टैंकर सहित 35 .45 लाख का मशरूका किया जब्त

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

थाना कबीर नगर पुलिस ने अवैध डीजल-पेट्रोल के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 14,100 लीटर ईंधन जब्त किया है। टैंकर सहित जब्त सामग्री की कुल कीमत 35,45,770 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

कान्हा ढाबा के पीछे दी गई दबिश

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कान्हा ढाबा के पीछे, ईपी रोलिंग मिल के पास भारी मात्रा में अवैध डीजल और पेट्रोल डंप कर रीसेलिंग और कटिंग का धंधा चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम ने घेराबंदी कर दबिश दी। मौके पर आरोपी बिना वैध दस्तावेज या लाइसेंस के ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित भंडारण कर रहे थे।

टैंकर में 12 हजार लीटर डीजल मिला

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 08 ड्रमों में 1,600 लीटर पेट्रोल, 03 ड्रमों में 500 लीटर डीजल और एक टैंकर वाहन क्रमांक उꪃ07 इअ 8727 में 12,000 लीटर डीजल बरामद किया। साथ ही 1 लाख 30 हजार रुपये नगद, 01 मोटर पंप, 02 कीप और 01 कटिंग ड्रम भी जब्त किया गया। कुल 14,100 लीटर ईंधन और उपकरणों की कीमत 35,45,770 रुपये है।

गिरफ्तार आरोपियों में ओमप्रकाश साव उर्फ कालिया, उम्र 38 वर्ष, निवासी उरला, उमेश साव, उम्र 55 वर्ष, निवासी बीरगांव, रामजी यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी दुर्ग और धर्मेन्द्र साव, उम्र 45 वर्ष, निवासी खुर्सीपार शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में थाना उरला और आमानाका में अवैध तेल कारोबार में पकड़े जा चुके हैं। उन पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज

थाना कबीर नगर में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3-एरर, 7-एरर एवं बीएनएस की धारा 287, 111 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है कि अवैध ईंधन कहां से लाया जा रहा था और कहां खपाने की तैयारी थी।

जेल के बाथरूम में बंदी ने किया आत्महत्या

जांजगीर-चांपा। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जिला जेल के अंदर एक कैदी का शव बाथरूम में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। घटना से जेल परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म मामले में एक दिन पहले ही उसे जेल में दाखिल किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय सामने आई जब सुबह सफाईकर्मी बाथरूम की सफाई के लिए पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर जेल स्टाफ ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

मध्यप्रदेश राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द

केस की जानकारी छुपाने का आरोप, भाजपा की आपत्ति पर रिटर्निंग अधिकारी का फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन फार्म में आपराधिक केस की जानकारी छुपाने के आरोप में रिटर्निंग अधिकारी ने यह कार्रवाई की। भाजपा की आपत्ति के बाद जांच में आरोप सही पाए जाने पर नामांकन निरस्त किया गया।

तेलंगाना के केस का नहीं किया उल्लेख : भाजपा ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्होंने नामांकन फार्म में तेलंगाना में दर्ज आपराधिक केस का उल्लेख नहीं किया और जानकारी छुपाई। रिटर्निंग अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच के बाद आपत्ति को सही मानते हुए नामांकन रद्द कर दिया।

बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों की जीत तय : मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से मध्यप्रदेश की राज्यसभा की तीनों सीटों पर अब भाजपा उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन एकमात्र उम्मीदवार थीं। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं बचा।

चुनाव आयोग के नियमों का हवाला : चुनाव नियमों के अनुसार उम्मीदवार को नामांकन फार्म में अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है। जानकारी छुपाने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है। भाजपा ने इसी नियम का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है।

रायगढ़ में नकली शराब का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, 2 लाख की अवैध शराब जब्त

"ऑपरेशन आघात" के तहत धनागर में पुलिस-आबकारी की संयुक्त छापेमारी, एक गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

रायगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने "ऑपरेशन आघात" के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतरारोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम धनागर में नकली शराब बनाने के संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 869 नग नकली शराब, 240 लीटर अवैध मदिरा कीमत करीब 2 लाख 16 हजार रुपये जब्त की। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि दो फरार हैं।

ब्रांडेड कंपनियों के लेबल में बिक रही थी नकली शराब

पुलिस को सूचना मिली थी कि दुष्यंत पटेल उर्फ पप्पू बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाकर खपा रहा है। टीम ने प्वाइंटर भेजकर दो पौव्वा गोवा शराब खरीदी। लेबल और होलोग्राम संदिग्ध मिलने पर आबकारी अधिकारियों ने जांच की। शराब में असामान्यता मिलने पर पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी। मौके से रॉयल स्टेज, आईबी, ब्लैक डॉग, गोवा, रिजर्व क्वार्टर, किंगफिशर बियर जैसे ब्रांड की पैकेजिंग में नकली शराब मिली।

कोरोना काल से चल रहा था कारोबार

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी दुष्यंत पटेल ने बताया कि वह भाई सुभाष पटेल और विनय सिंह के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से शराब खरीदता था। उसमें स्प्रिट, अन्य पदार्थ और रेड लेबल चायपत्ती मिलाकर मात्रा बढ़ाई जाती थी। पुरानी बोतलों को साफ कर डुप्लीकेट लेबल और नकली होलोग्राम लगाकर पैक किया जाता था। तैयार नकली शराब को कोचियों के जरिए असली के साथ बाजार में खपाया जाता था। आरोपी ने स्वीकार किया कि कोरोना काल से यह कारोबार चल रहा था।

फरार आरोपियों की तलाश जारी

थाना कोतरारोड़ में दुष्यंत पटेल उर्फ पप्पू, सुभाष पटेल एवं विनय ठाकुर के खिलाफ धारा 61(2), 336(3), 336(4), 340(2), 275 भारतीय न्याय संहिता तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36-च, 34(1)(क)(ख) एवं 59-क के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दुष्यंत पटेल, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम धनागर को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया। फरार सुभाष पटेल और विनय सिंह की तलाश जारी है।

कार्रवाई में 869 नग विभिन्न पैमानों की करीब 240 लीटर नकली शराब के साथ 560 शराब बोतलों के ढक्कन, स्प्रिट के ड्रम, केटली, खाली बोतलें जब्त हुईं। नकली शराब की बिक्री से करीब 2 लाख 16 हजार 245 रुपये का मुनाफा होना बताया गया।

एसएसपी बोले : जीरो टॉलरेंस की नीति

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर हर सदस्य पर कठोर कार्रवाई होगी। ऑपरेशन आघात के तहत ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई में थाना साइबर, कोतरारोड़ और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम शामिल रही।

सहस्त्रनाम लेखन करने वाले 75 श्रद्धालुओं का किया सम्मान, वैदिक मूल्यों के संरक्षण का दिया संदेश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अधिक मास के पावन अवसर पर गजानन महाराज मंदिर, आमापारा में सहस्त्रनाम लेखन करने वाले श्रद्धालुओं के सम्मान में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहस्त्रनाम लेखन के माध्यम से सनातन संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश दिया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि एवं वक्ता साइंस कॉलेज दुर्ग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक आचार्य सुरेशचंद्र शर्मा थे। विशेष अतिथि के रूप में श्री राम मंदिर गांधी चौक के मुख्य पुजारी संतोष कुमार पाठक, श्री साई मंदिर समिति सिविल लाइन कसारीडीह के अध्यक्ष धनेंद्र कांत चंदेल तथा सचिव धीरेंद्र शर्मा उपस्थित रहे।

सहस्त्रनाम लेखन कार्यक्रम का आयोजन श्री राम मंदिर के उपाध्यक्ष प्रकाश कानाबार के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें दुर्ग-भिलाई समर्थ ज्ञान पाठशाला की मुख्याध्यापिका श्रीमती रोहिणी पाटणकर, गजानन मंदिर के पूर्व अध्यक्ष श्रीराम कुलकर्णी, श्रीमती संगीता कुलकर्णी एवं श्रीमती पूणिर्मा पाटणकर का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में 75 महिलाओं तथा बालक-बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दी।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत से हुआ। श्रीराम कुलकर्णी ने अतिथियों का शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इसके पश्चात आयोजिका श्रीमती रोहिणी पाटणकर ने सहस्त्रनाम लेखन के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते

हुए बताया कि यह साधना मन को एकाग्र करने एवं धार्मिक संस्कारों को सुदृढ़ करने का प्रभावी माध्यम है।

मुख्य अतिथि आचार्य सुरेशचंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में सनातन धर्म के वैदिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि साइंस कॉलेज से सेवानिवृत्ति के बाद वे अमरकंटक स्थित मंदिर में निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया। सभी 75 श्रद्धालुओं ने विभिन्न देवी-देवताओं के सहस्त्रनामों का शुद्ध उच्चारण के साथ लेखन कर अपनी प्रतियां जमा कीं। उत्कृष्ट सहभागिता के लिए मुख्य अतिथि द्वारा सभी को पुरस्कृत किया गया तथा विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तकें भी भेंट की गई। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व गत माह भी 50 श्रद्धालुओं को प्रकाश कानाबार द्वारा सम्मानित किया गया था। उनके मार्गदर्शन में दुर्ग-भिलाई क्षेत्र की भावी पीढ़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस धार्मिक अभियान से जुड़ रही है।

कार्यक्रम के सफल संचालन में श्रीमती संगीता कुलकर्णी एवं श्रीमती पूणिर्मा पाटणकर ने महिलाओं एवं बच्चों का मार्गदर्शन किया। अंत में श्रीमती संगीता कुलकर्णी ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश रडके, पूर्व अध्यक्ष श्रीराम कुलकर्णी, मंदिर पुजारी बेडेकर गुरुजी, श्रीमती सुनीता, संगीता कथडे, संगीता भेंडे, सरोज पहाड़े, शिवानी जोशी, लक्ष्मी दुबे, श्वेता जोशी, सरोज अग्रवाल, नीलिमा पट्टलवार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

खास खबर

ऑल इंडिया नेशनल डांस एवं म्यूजिक कॉम्पिटिशन" में श्री शंकरा विद्यालय की अद्रिजा को मिला प्रथम पुरस्कार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया नेशनल डांस, म्यूजिक एंड फाइन आर्टस कॉम्पिटीशन "तारांगन" में श्री शंकरा विद्यालय, सेक्टर- 10 में अध्यनरत क्लास- 2 की छात्रा अद्रिजा दत्ता ने सब जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जीता है। उसे सेमी क्लासिकल भरतनाट्यम और फोक डांस मराठी लावनी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। यह प्रतियोगिता 5 जून से 7 जून तक देहरादून में हुई।

छात्र अद्रिजा को बचपन से ही नृत्य और संगीत का शौक है। 7 वर्ष की नन्ही बालिका तथा गुरु अन्वेषा भाटिया के डांस एकेडमी की छात्रा अद्रिजा ने पिछले दो वर्षो में कई कॉम्पटीशन में प्राइज जीता । गुरु अन्वेषा के निर्देशन में अद्रिजा लगातार पुरस्कार जीत रही है। पिछले वर्ष हुनर भिलाई में अद्रिजा को प्रथम पुरस्कार के रूप में 11000 रुपए की राशि मिली। वहीं केपीएस के प्रज्ञोत्सव के दो कैटेगरी में उसने प्रथम पुरस्कार और एक में द्वितीय पुरस्कार जीता। राजनांदगांव के कौशिकी कार्यक्रम में भी अद्रिजा ने प्रथम पुरस्कार जीता। अद्रिजा की इस सफलता पर स्कूल प्रबंधन ने उसे बधाई दी है। प्रबंधन ने गर्व महसूस करते हुए कहा है कि अद्रिजा को उसकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण ही यह उपलब्धि हासिल हुई है। अद्रिजा के पिता देबदूति दत्ता, वेदांता में केमिकल इंजीनियरिंग हैं वही माता काजल ग्रहणी हैं। अद्रिजा के माता-पिता ने अपनी बेटी की इस सफलता पर गर्व जताया है।

नि :शुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ, एक सप्ताह तक मिलेगा स्वास्थ्य लाभ

दुर्ग। "मानव सेवा ही माधव सेवा है" के पावन उद्देश्य को लेकर जिला साहू संघ, दुर्ग द्वारा साहू सदन, केलाबाड़ी दुर्ग में एक सप्ताहीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन, सुजोक एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ सोमवार को भक्त माता कर्मा की पूजा-अचर्ना एवं आरती के साथ किया गया। जिला साहू संघ द्वारा लोक कल्याण, रोग निदान एवं सर्वजन हिताय की भावना से आयोजित इस शिविर में घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, वैरिकोज वेन्स, लकवा, बवासीर सहित विभिन्न गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर का आयोजन 8 जून से 14 जून तक किया जाएगा। उपचार हेतु प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा सायं 4:30 बजे से रात 9:00 बजे तक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

जिला साहू संघ के जिलाध्यक्ष नंदलाल साहू ने बताया कि शिविर में सभी धर्म, समुदाय एवं पंथ के लोग उपचार का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि उपचार पूरी तरह निःशुल्क है, केवल पंजीयन के समय 100 रुपये का अंशदान लिया जाएगा। शिविर के शुभारंभ अवसर पर दुर्ग जिला साहू संघ के प्रमुख सलाहकार रमेश साहू (पूर्व प्रदेश कायर्कारी अध्यक्ष), डॉ. जी.आर. साहू, श्रीमती यमला साहू, लखन साहू, इंजीनियर प्रेम शंकर साहू, संगठन सचिव एवं पार्षद श्रीमती सविता पोषण साहू ने इस अभिनव जनसेवा पहल की सराहना करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष डॉ. भारती साहू, छात्रावास अधीक्षक सुनील साहू, जिला सह मीडिया प्रभारी पोषण साहू, प्रचार-प्रसार सचिव कुलदीप साहू, के.पी. साहू, महिला जिला संयोजिका श्रीमती ललेश्वरी साहू, श्रीमती भुनेश्वरी साहू, हेमलाल साहू सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित रहे। शिविर में उपचार हेतु पूर्व डीएसपी सुभाष चौधरी, कुंदन साहू, तीरथ साहू, शेफाली सरकार, सैय्यद अहमद अली, मीनाक्षी साहू, ममता बारापात्रे, दाऊराम, अयोध्या प्रसाद, श्यामलाल, बिसेसर राम सिन्हा, दिनेश चंद्र, गुलाब राव, देवाशीष सरकार सहित सैकड़ों नागरिकों ने पंजीयन कराया और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की इच्छा जताई।

छग राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई 18 को

दुर्ग। महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा आगामी 18 जून को दुर्ग जिले में एक वृहद जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यह जनसुनवाई 18 जून को पूर्वान्ह 11 बजे से बाल गृह परिसर, पांच बिल्डिंग स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, दुर्ग के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। इस सुनवाई की अध्यक्षता अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक एवं सदस्यगण श्रीमती ओजस्वी मण्डावी व सुश्री दीपिका शोरी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी, जिसमें महिला उत्पीड़न से जुड़े कुल 49 निर्धारित प्रकरणों पर गंभीरता से सुनवाई कर उनका मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।

स्वास्थ्य कर्मियों ने विभिन्न कैडर की वेतन विसंगति दूर करने उठाई मांग

8वें वेतन आयोग से पहले पिछली तमाम विसंगति दूर करने शासन को भेजी जानकारी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कैडरों की वेतन विसंगति कई वर्षो से लंबित है। ऐसे मे केंद्र सरकार ने 8 वां वेतन आयोग गठित कर दिया है, अभी समय है कि पिछली वेतन विसंगति को दूर कर आगामी 8 वें वेतनमान मे सभी कैडरों की वेतन विसंगति दूर की जाए।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग मे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक व स्वास्थ्य संयोजक का ग्रेड पे छठवें वेतनमान मे पहले 1900 था लेकिन जबकि अन्य विभागों में समान योग्यताधारी तृतीय वर्ग कर्मचारी का ग्रेड पे 2400 कर दिया गया था। प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लंबे आंदोलन पश्चात इसे 2200 किया गया हालांकि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक व स्वास्थ्य संयोजक का केंद्र व अन्य राज्यों मे 2400 ग्रेड पे निर्धारित है। इसमें भी 200 रुपए कम करके 7 वें वेतन आयोग में स्लैब मे एक स्तर पीछे कर दिया गया है।

महामंत्री सैय्यद असलम ने कहा कि इस कैडर के साथ चार कैडर पदोन्नत वाले ओर प्रभावित हुए। छठवें वेतन मान में स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सुपरवाइजर पुरुष और महिला स्वास्थ्य पयर्वेक्षक का 2800 ग्रेड पे केंद्र व अन्य राज्यों में निर्धारित है। छत्तीसगढ़ सरकार मे 2400 रुपये निर्धारित किया। जिससे 7वे वेतनमान में इस संवर्ग को एक स्तर पीछे कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य सुपरवाइजर एल एच व्ही और महिला स्वास्थ्य पयर्वेक्षक से पदोन्नत पद बी ई टी ओ अर्थात खंड विस्तार स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण अधिकारी का वेतनमान छठवें आयोग में 2800 किया गया। जबकि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में इसका ग्रेड पे 4200 था। इसे 7 वें वेतनमान में एक स्तर पीछे कर दिया है। इसी क्रम में अन्य संवर्गो स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, नेत्र चिकित्सा अधिकारी, कुष्ठ कार्यकर्ता, ड्रेसर, वाहन चालक, लिपिक वर्गीय कर्मचारी और एक्स-रे टेक्नीशियन, डायलिसिस संवर्गो, ईसीजी टेक्नीशियन, चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदो के साथ विसंगति करते हुए एक पदक्रम पीछे का वेतनमान निर्धारित किया गया। इस वजह से छत्तीसगढ़ प्रदेश मे स्वास्थ्य अमला प्रत्येक वेतनमान लागू होने के समय एक वेतन लेवल पीछे रह गया। हालांकि पांचवें वेतनमान में अन्य विभागों के तृतीय श्रेणी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान के समकक्ष या इससे कम वेतनमान पर थे। हर वेतनमान मे एक पदक्रम आगे बढ़ा दिए गए।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार विभिन्न कायर्काल में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की लंबे आंदोलन पश्चात इंदिरा मिश्रा समिति ओर राउत कमेटी ने अपनी सिफारिशों मे इस बात का उल्लेख भी किया कि वेतन विसंगति हुई है और स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग वेतन आयोग गठन किया जाना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मे अनेक कैडर है जो अन्य विभागों के तुलनात्मक अध्ययन पर शैक्षिक, तकनीकी रूप से उनसे समकक्ष अथवा ज्यादा प्रभावी है। इसके बावजूद प्रदेश मे हर वेतनमान लागू करने के समय इनकी वेतन विसंगति दूर नहीं करना अपने आप मे एक बड़ा सवाल है। प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने कहा कि इसका खामियाजा हमें सेवाकाल के दौरान हो रहा है।

सेवानिवृत्त के दौरान भी पेंशन निर्धारित होते समय विभिन्न देयकों के मिलने वाली राशि और पेंशन राशि सभी पर असर पड़ रहा है। विभाग मे भी समकक्ष योग्यता धारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों मे भी वेतन विसंगति है। जिससे समयमान वेतनमान 10 वर्ष उपरांत, 20 वर्ष उपरांत और 30 वर्ष उपरांत मिलने वाला वेतनमान निर्धारण में 2000 से लेकर 5000 तक अंतर देखने में मिलता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ लगातार शासन से इस गुत्थी और वेतन विसंगति सुधार करने आंदोलन करते हुए केंद्र के समान वेतनमान देने अपील करते आ रहा है। 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इन विसंगतियों को दूर किया जा सकता है, जिन्हें पिछले तीन वेतनमान मे अनदेखा किया गया है।

19वां छग टैक्स बार काउंसिल अधिवेशन में जीएसटी के कानूनी पहलुओं पर हुई विस्तृत चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

टैक्स बार एसोसिएशन दुर्ग के तत्वावधान में 19वां छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल अधिवेशन रविवार को शिवनाथ नदी के समीप स्थित पृथ्वी पैलेस में आयोजित किया गया। अधिवेशन में प्रदेशभर से आए अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं कर सलाहकारों ने भाग लिया तथा जीएसटी कानून से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया।

कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत सुश्री निधि यादव एवं सुश्री प्रेमलता द्वारा तिलक-रोली लगाकर किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सतीश कुमार अग्रवाल थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मूलचंद जैन ने की। विशेष अतिथि के रूप में संजय शर्मा उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा एवं महासचिव शिव सोनी ने अतिथियों के साथ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रतिष्ठा ठाकुर ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन श्रीचंद लेखवानी एवं शांति श्रीश्रीमाल ने किया। अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अधिवक्ताओं एवं सीए सदस्यों का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। तकनीकी सत्र में जीएसटी अधिनियम 2017 के अध्याय-14 (निरिक्षण, तलाशी, जब्ती एवं गिरफ्तारी) विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। सत्र के वक्ता संजय शर्मा रहे तथा अध्यक्षता राजेश्वर राव ने की।

अपने व्याख्यान में संजय शर्मा ने कहा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जीएसटी विभाग द्वारा निरीक्षण एवं तलाशी की कार्रवाई के दौरान कर सलाहकारों को अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए तथा यदि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत विभाग एवं पोर्टल पर दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि व्यवसायियों के जीएसटी पोर्टल पर ई-मेल एवं मोबाइल नंबर व्यवसायी के ही दर्ज होने चाहिए, ताकि विभागीय सूचनाएं सीधे संबंधित व्यक्ति तक पहुंच सकें।

कार्यक्रम में प्रभांक ठाकुर, एस.एन. यदु, एल.एन. नेमा, धर्मेश शाह, दिलीप जैन, संजय चक्रवर्ती, आशीष मढ़रिया, प्रेमचंद देवांगन, राधेश्याम देवांगन, आनंद दीक्षित, मिलापचंद ओसवाल, किशोर पारख, एम.के. पाढ़ी, मोहम्मद इलियास, राजेश दीवान, नरेंद्र शर्मा, नितिन रुगटा, राकेश ढोडी, सुशील जैन, विजयंत पटेल, आशीष खंडेलवाल, संजय पांडे, दिग्विजय सिंह, भागवत गिरि गोस्वामी, दुष्यंत गिरि, सुनील विश्वकर्मा, अब्दुल नूर खान, मोहम्मद सलीम, संजय कंदोई, प्रवीण शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट उपस्थित रहे।

शहर के विभिन्न वार्डो में विकास कार्यो की सौगात, महापौर बाघमार ने किया भूमिपूजन

सड़क, नाली, पुलिया व सीसी रोड निर्माण से नागरिकों को मिलेगी बेहतर सुविधा

जनसुविधाओं के विस्तार के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध, विकास कार्यों में नहीं होगी कोई कमी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न वार्डो में विकास कार्यो को लगातार गति दी जा रही है। इसी क्रम में शनिवार शाम महापौर अलका बाघमार ने लोककर्म विभाग प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, पार्षद नरेंद्र बंजारे, शेखर चन्द्राकर, विजयंत पटेल, ललित ढीमर, रंजीता पाटिल, उपअभियंता प्रेरणा दुबे तथा क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में विभिन्न निर्माण कार्यो का विधिवत भूमिपूजन किया।

महापौर ने वार्ड क्रमांक 56 में आलोक साहू के घर से हेमलता ठाकुर के घर तक सड़क निर्माण कार्य का

शुभारंभ किया। इसके अलावा बघेरा क्षेत्र में शैलेंद्र किराना स्टोर्स से धरम साहू के घर तक सड़क निर्माण तथा इंदिरा नगर में शिव मंदिर से गुधारी निर्मलकर के घर तक सड़क एवं अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण कार्यो की आधारशिला रखी गई। विभिन्न स्थानों पर आरसीसी नाली, पुलिया एवं सीसी रोड निर्माण कार्यो का भी भूमिपूजन किया गया।

इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 05 में महर्षि दयानंद स्कूल के पास एवं गया बाई स्कूल के पीछे नाली और सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। वहीं मरारपारा क्षेत्र में नंदराम साहू के घर से निशांत देवांगन चौक तक सीसी रोड, नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया गया। इन कार्यो के पूर्ण होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, जल निकासी व्यवस्था में सुधार आएगा तथा नागरिकों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी।

इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा सभी वार्डो में संतुलित और समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़क, नाली, पुलिया तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यो को प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और प्रत्येक वार्ड की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं पाषर्दो ने क्षेत्र में विकास कार्यो की शुरुआत पर निगम प्रशासन एवं महापौर का आभार व्यक्त किया। वहीं स्थानीय नागरिकों ने लंबे समय से लंबित मांगों पर कार्य प्रारंभ होने पर प्रसन्नता जताते हुए महापौर एवं निगम प्रशासन को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

भिलाई के डॉक्टर की पुस्तक अमेजन पर बेस्ट सेलर, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में बनी नंबर-1

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र अब इस्पात उत्पादन के साथ चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन में भी अपनी पहचान बना रहा है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. दीपक कुमार दासमहापात्र की पुस्तक क्वालिटी मैनेजमेंट इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड एसओपी ऑफ ब्लड सेंटर ने अमेजन पर हेमेटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन श्रेणी में #1 बेस्ट सेलर का स्थान हासिल किया है।

4 मई को हुआ था प्रकाशन : इनोवेटिव पब्लिकेशन द्वारा 4 मई 2026 को प्रकाशित इस पुस्तक को रक्त सेवा संचालन और गुणवत्ता प्रबंधन की महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तक माना जा रहा है। इसमें ब्लड सेंटर के संचालन, गुणवत्ता मानकों, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। चिकित्सा शिक्षकों, पीजी विद्यार्थियों, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट और

ब्लड सेंटर प्रबंधकों के बीच इसे सराहना मिल रही है।

एनएबीएच मानकों पर आधारित : डॉ. दासमहापात्र जेएलएन चिकित्सालय में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में कंसलटेंट हैं। एमबीबीएस और एमडी के साथ वे अस्पताल प्रबंधन, कॉपीरेट लॉ, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में भी विशेषज्ञता रखते हैं। पुस्तक के सह-लेखक संदीप कुमार पांडे, डॉ. अनुराधा पांडा और डॉ. बबीता एक्का हैं।

जेएलएन चिकित्सालय का ब्लड सेंटर एनएबीएच मान्यता प्राप्त है। यह छत्तीसगढ़ और सेल अस्पतालों की श्रृंखला में अपनी तरह का पहला ब्लड सेंटर है। पुस्तक को एनएबीएच और जेसीआई जैसे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।

व्यावहारिक मार्गदर्शक बनी पुस्तक : पुस्तक में ब्लड सेंटर लाइसेंसिंग, ओएनडीएलएस पोर्टल पंजीकरण, गुणवत्ता नीति, ऑडिट प्रणाली और प्रयोगशाला स्तर की जटिल चुनौतियों के समाधान शामिल हैं। एबीओ विसंगतियों, पॉजिटिव डीएटी परिणामों और रक्त अनुकूलता से जुड़े मामलों के लिए त्वरित संदर्भ तालिकाएँ और विस्तृत प्रोटोकॉल दिए गए हैं। डॉ. दासमहापात्र के अनुसार सुरक्षित रक्त सेवा केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे चिकित्सकों, तकनीशियनों, नर्सिंग स्टाफ और स्वैच्छिक रक्तदाताओं की समर्पित श्रृंखला काम करती है। पुस्तक के माध्यम से उन सभी के योगदान को रेखांकित किया गया है।

भिलाई से प्रकाशित इस पुस्तक की राष्ट्रीय सफलता भिलाई इस्पात संयंत्र और जेएलएन अस्पताल की ज्ञान परंपरा का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि भिलाई अब केवल इस्पात निर्माण का नहीं, ज्ञान, नवाचार और चिकित्सा उत्कृष्टता का भी केंद्र बन रहा है।

पट्टाविहीन परिवारों को अब मिलेगा मालिकाना हक : भोजराज सिन्हा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, जो वर्षो से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भूमि का वैध स्वामित्व नहीं है। अब ऐसे पात्र पट्टाविहीन परिवारों को शासन द्वारा मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

सिन्हा ने बताया कि आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 के अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 के पूर्व से निवासरत परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम भिलाई के

नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने जनप्रतिनिधियों व राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया

सभी वार्डो में व्यापक सर्वे अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पट्टा प्राप्त होने के बाद गरीब एवं भूमिहीन परिवारों को न केवल अपनी भूमि पर वैधानिक अधिकार मिलेगा, बल्कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभभी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही बैंक से ऋण लेकर अपने कच्चे मकानों को पक्का बनाने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

नेता प्रतिपक्ष सिन्हा ने निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सर्वे दल को सही एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पात्र परिवारों की पहचान में सहयोग करें, ताकि शासन की इस ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल पट्टा वितरण का कार्य नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायी आशियाने का अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री साय ने की 'मोहला' ब्रांड की सराहना, कहा- आत्मनिर्भरता का प्रतीक

महिला समूहों और FPO के उत्पाद सीएम को भेंट, महुआ अचार और रागी लड्डू शामिल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के स्व-सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा तैयार 'मोहला' ब्रांड के उत्पादों की सराहना की है। कलेक्टर श्रीमती तूलिका प्रजापति और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर ने मुख्यमंत्री को ब्रांड के उत्पाद भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इसे स्थानीय उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का सशक्त माध्यम बताया।

महुआ अचार से कोदो चावल तक उत्पाद शामिल

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों और एफपीओ द्वारा स्थानीय एवं पोषणयुक्त उत्पादों को 'मोहला' ब्रांड के रूप में नई पहचान दी गई है। ब्रांड के अंतर्गत महुआ का अचार, जंगल का शुद्ध शहद, रागी के लड्डू, मिलेट्स कुकीज, कोदो चावल, रागी का आटा और अन्य स्थानीय उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं।

महुआ उत्पादों की विशेष प्रशंसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी एवं वनांचल क्षेत्र में महिलाओं और किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्वयं का जिला ब्रांड विकसित करना प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने महुआ से निर्मित उत्पादों की विशेष प्रशंसा की। कहा कि महुआ प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का हिस्सा है। आधुनिक पैकेजिंग और ब्रांडिंग से इसे बाजार उपलब्ध कराना स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने का उत्कृष्ट प्रयास है।

'वोकल फॉर लोकल' का उदाहरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को स्थानीय पहचान से जोड़कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बाजारों तक पहुंचाना 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को साकार करने का प्रभावी उदाहरण है। उन्होंने 'मोहला' ब्रांड से जुड़े सभी स्व-सहायता समूहों, एफपीओ और जिला प्रशासन को बधाई दी।

बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास

कलेक्टर श्रीमती तूलिका प्रजापति ने कहा कि 'मोहला' ब्रांड जिले की महिलाओं और किसानों की मेहनत, कौशल और उद्यमशीलता का प्रतीक है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ रही है और रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर ने बताया कि उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 'मोहला' को जिले की विशिष्ट पहचान के रूप में स्थापित किया जाएगा।

खास खबर

वित्त मंत्री चौधरी ने शौर्य चक्र से सम्मानित छग पुलिस के जांबाज अधिकारियों को दी बधाई

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट एवं इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि यह सम्मान दोनों अधिकारियों के अद्वितीय साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का गौरवपूर्ण प्रमाण है। विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्होंने जिस वीरता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है, वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के इन वीर अधिकारियों ने अपने साहसिक कार्यों से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। उनका यह सम्मान छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रसेवा और कर्तव्यपरायणता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दोनों अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश को उनके शौर्य और समर्पण पर गर्व है।

4 साल से बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित, सहायक ग्रेड-03 के कर्मचारी हुआ बर्खास्त

रायपुर। लंबे समय से बिना अनुमति और बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षा विभाग के कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा ने सहायक ग्रेड-03 सूरज कुमार भगत की सेवा समाप्त कर दी है। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

जानकारी के अनुसार शासकीय हाई स्कूल लक्ष्मणगढ़, विकासखंड उदयपुर में पदस्थ सूरज कुमार भगत 17 मार्च 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति को लेकर विभाग द्वारा समय-समय पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। साथ ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने निर्धारित अवधि में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित कर्मचारी लंबे समय से बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहे और अपनी अनुपस्थिति के समर्थन में कोई वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत श्री भगत की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया।

नई पीढ़ी को संस्कृति, कला और लोक परंपराओं की जानकारी देना समय की आवश्यकता है-बृजमोहन अग्रवाल

प्रतिभा, परंपरा और सृजनशीलता का उत्सव, रंग, रचनात्मकता और संस्कृति का महोत्सव बना आकार-2026

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और आधुनिक रचनात्मकता के अद्भुत संगम का प्रतीक बना संस्कृति विभाग का बहुप्रतीक्षित कला प्रशिक्षण शिविर आकार-2026 रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रतिभागियों की शानदार प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हो गया। 25 मई से 9 जून तक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, रायपुर में आयोजित इस 16 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेशभर से आए 1281 प्रतिभागियों ने 16 विभिन्न कला विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को नई दिशा दी।

समापन समारोह में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्षा सुश्री मोना सेन, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे तथा उप संचालक प्रताप चंद्र पारख सहित बड़ी संख्या में कला प्रेमी, प्रशिक्षु एवं अभिभावक उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2004 में संस्कृति मंत्री रहते हुए उन्होंने आकार प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और लोक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह पहल प्रारंभ की गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ऐसे आयोजन प्रदेश के सभी संभागों में आयोजित किए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषणों, हस्तशिल्प के लिए स्थायी विक्रय केंद्र भी विकसित किए जाने चाहिए, जिससे कलाकारों को आर्थिक लाभ मिल सके और लोग छत्तीसगढ़ के आभूषण और हस्तशिल्प को देख और खरीद सकें।

श्री अग्रवाल ने बच्चों को मिट्टी और प्रकृति से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जिस दिन बच्चे मिट्टी से जुड़ना और मिट्टी से सृजन करना सीख जाएंगे, उनका जीवन आनंद और संवेदनशीलता से भर जाएगा। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, कला और लोक परंपराओं की जानकारी देना समय की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि आकार केवल एक प्रशिक्षण शिविर नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककलाओं, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धित करने का एक सशक्त माध्यम है। वर्ष 2004 से लगातार आयोजित हो रहा यह कार्यक्रम युवाओं में सृजनशीलता और सांस्कृतिक चेतना विकसित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पंजीयन शुल्क को 200 रुपये से घटाकर मात्र 100 रुपये किया गया। साथ ही दिव्यांग एवं अनाथ बच्चों के लिए विशेष रियायत भी प्रदान की गई, जिससे समाज के सभी वर्गों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल सके। आकार-2026 ने इस वर्ष पारंपरिक लोक कलाओं और आधुनिक तकनीक के बीच एक सुंदर सेतु का निर्माण किया। जहां एक ओर प्रतिभागियों ने टेराकोटा, जूट शिल्प, गोदना कला, रजवार भित्ति चित्र, मंडला एवं मांडना कला, भरथरी गायन और कथक जैसी विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कला की नवीनतम तकनीकों से भी परिचित कराया गया।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि बृजमोहन अग्रवाल ने सभी कला गुरुओं एवं प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने प्रशिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया। समापन अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम ने पूरे वातावरण को लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर कर दिया। प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। सुवा नृत्य, कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, बांसगीत, भरथरी गायन तथा लोकसंगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर तक मंत्रमुग्ध रखा। पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्यों की मधुर ध्वनि और कलाकारों की ऊर्जा ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

शिविर में प्रदेश के प्रतिष्ठित कला गुरुओं ने प्रशिक्षण प्रदान किया। एआई आर्ट का प्रशिक्षण वल्कल्पति जेस्सी, क्ले एवं टेक्सचर आर्ट सुश्री अलका हनवत, पेंटिंग राकेश पुजारी, बोनसाई कला अनिल वर्मा, भरथरी गायन प्रांजल सिंह, कथक नृत्य चिरंजीव हलधर, मंडला एवं मांडना आर्ट श्रीमती कविता यादव, रजवार भित्ति चित्र कला श्रीमती प्रतिमा डहरवाल, जूट एवं गोदना शिल्प श्रीमती कल्पना यादव, पारंपरिक गहना निर्माण एवं वुडन ट्राइबल आर्ट डॉ. शुभ्रा मिश्रा, लोकनृत्य एवं लोकसंगीत तेजराम साहू, हस्तकढ़ाई एवं शिल्प डिजाइनिंग प्रेमलता सिंह, टेराकोटा श्री विमल फुटान, लिप्पन आर्ट एवं पचवाई कला निधि अग्रवाल, वाद्य यंत्र रिखी क्षत्रीय तथा क्रोशिया कला का प्रशिक्षण सीमा रायजादा ने दिया।

आकार-2026 ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा भी है। 1281 प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता, अनुभवी कला गुरुओं का मार्गदर्शन और लोक संस्कृति से सराबोर प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को रंग, रचनात्मकता और परंपरा के सच्चे महाकुंभ में परिवर्तित कर दिया। यह आयोजन न केवल कला प्रशिक्षण का मंच बना, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास भी सिद्ध हुआ।

भारतीय जूडो महासंघ के अध्यक्ष बने मुकेश, छग समर्थित पैनल की जीत

शुल्क में भारी कटौती की घोषणा, साई से अकादमी खोलने का आश्वासन मिला

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-नईदिल्ली

भारतीय जूडो महासंघ के चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ समर्थित उम्मीदवार मुकेश कुमार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। शनिवार 8 जून को दिल्ली के लेमन ट्री होटल में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चुनाव संपन्न हुआ।

प्रमुख पदों पर निर्वाचन

असम के बनी बता दास अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को भारी मतों से हराकर महासचिव चुने गए। महाराष्ट्र के शैलेश तिलक कोषाध्यक्ष पद पर विजयी हुए। जेएसडब्ल्यू की आईआईएस स्पोर्ट्स अकादमी की चेयरपर्सन श्रीमती मनीषा मल्होत्रा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुईं। मुकेश कुमार जूडो यूनियन ऑफ एशिया के महासचिव भी हैं।

मान्यता का रास्ता साफ

इस चुनाव से भारतीय जूडो महासंघ को खेल मंत्रालय से मान्यता मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अब तक मान्यता न होने के बावजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनुदान देता रहा है। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 6 साल पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ की मान्यता समाप्त कर दी थी। तब से विभाग ने कोई अनुदान नहीं दिया। इसके बावजूद प्रदेश संघ अपने संसाधनों से गतिविधियां संचालित कर रहा है। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत रहे हैं।

खिलाड़ियों को राहत, शुल्क में कटौती

अध्यक्ष बनते ही मुकेश कुमार ने जूडो खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों और रेफ्रियों से लिए जाने वाले भारी शुल्क में कटौती की घोषणा की। इस फैसले का देशभर में स्वागत हो रहा है।

छग में अकादमी खोलने की मांग

चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी, महासचिव शंभू राम स्वामी और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी शेख शरीफ ने भाग लिया। प्रदेश संघ ने मुकेश कुमार को बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ में जूडो के विकास के लिए सहयोग मांगा। प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव ने साई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मयंक कुमार श्रीवास्तव से भेंट की। छत्तीसगढ़ में साई की खेल अकादमी, स्पेशल एक्सीलेंस सेंटर और खेलो इंडिया के तहत संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। श्री श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया कि जल्द छत्तीसगढ़ में जूडो के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और अकादमी भी खोली जाएगी।

अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई : चैन माउंटेन मशीन व हाईवा जप्त

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में खनिज संसाधनों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग की केंद्रीय खनि उड़नदस्ता एवं जिला स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा जिला गरियाबंद में बड़ी कार्रवाई की गई है।

खनिज विभाग के सचिव और संचालक के निर्देशानुसार केंद्रीय खनि उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने 8 जून को औचक निरीक्षण के दौरान जिला गरियाबंद के तहसील राजिम अंतर्गत ग्राम कुरुसकेरा स्थित पैरी नदी में गौण खनिज साधारण रेत के अवैध उत्खनन एवं मशीनों के माध्यम से नियम विरुद्ध रेत उत्खनन का मामला पाया। जांच के दौरान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए तीन चौन माउंटेन मशीनों को जप्त कर सील किया गया। साथ ही खदान संचालक एवं मशीन मालिकों को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध रेत परिवहन में संलिप्त एक हाईवा वाहन को भी जप्त कर राजिम थाना में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। कार्रवाई के दौरान केंद्रीय खनि उड़नदस्ता की संयुक्त जांच टीम तथा जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम उपस्थित रही।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा खनिज संपदा के नियमानुसार उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा तथा दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। खनिज साधन विभाग के सचिव ने कहा कि प्रदेश में खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सतत निगरानी की जा रही है। विभागीय अमला एवं उड़नदस्ता दलों को नियमित निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ : अब एक कॉल पर सुनी जाएगी जनता की हर समस्या

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री ने कहा - सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मिलेगी नई मजबूती

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य की बहुप्रतीक्षित सीएम हेल्पलाइन 1076 का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन प्रणाली के आधिकारिक लोगो का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्यगण तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या सुनी जाए, उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शासन-प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्रदेशभर से प्राप्त शिकायतों, सुझावों और जनप्रतिसाद ने एक प्रभावी, सशक्त एवं स्थायी जनसंपर्क तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी सोच के साथ सीएम हेल्पलाइन प्रणाली विकसित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे तथा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक मोबाइल के माध्यम से आसानी से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपने व्यापक दायरे के कारण विशेष महत्व रखती है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं तथा 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा। यदि किसी शिकायतकर्ता को प्राप्त समाधान से संतोष नहीं होगा, तो संबंधित शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण एवं जांच के लिए अग्रेषित हो जाएगी। इससे शिकायतों के सतही निराकरण की संभावना समाप्त होगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रणाली 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित रहेगी। इसके संचालन के लिए तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सचिव स्तर के अधिकारी डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी नियमित निगरानी करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय भी इसकी सतत मॉनिटरिंग करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायत निवारण का माध्यम नहीं है, बल्कि जनभागीदारी को सशक्त बनाने का एक प्रभावी मंच भी है। प्रदेशवासी राज्य के विकास से जुड़े अपने सुझाव भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा कर सकेंगे, जिससे नीति निर्माण और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव एवं सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग राहुल भगत ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन प्रणाली की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों और विशेषताओं की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय का रा.प्र.क्र. ..../अ-6/वर्ष 2025-26 में आवेदिका/आवेदक विष्णु कुमार साहू आ./ध.प. स्व. फगुवाराम साहू निवासी-रामनगर सुपेला भिलाई तह. दुर्ग व जिला दुर्ग द्वारा ग्राम कोहका प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. कोहका व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 5186/5 रकबा 0.010 हे. है। जो भूमिस्वामी फगुवाराम साहू आ. पलटन साहू के नाम पर दर्ज है। जिसमें भूमिस्वामी फगुवाराम साहू आ० पलटन साहू की मृत्यु दिनांक 17/07/2019 को फौत हो जाने के कारण मृतक का नाम खाते से विलोपित कर उसके वैध वारिसानो का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि फौती नामांतरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 10/06/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21/05/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.क्र./202605101000174/ब-121/वर्ष 2025-26)

इस न्यायालय के रा.प्र.क्रं. 202605101000174/ब-121/वर्ष 2025-26 आवेदक-सरपंच ग्राम पंचायत बासीन पता बासीन द्वारा ग्राम बासीन प.ह.न. 11, रा.नि.मं. जेवरा सिरसा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 890, 895 रकबा 0.81, 0.43 हे. भूमि नंदजी पिता हीरामन के नाम पर अभिलेख में दर्ज है, जिसे ग्राम पंचायत आवश्यक हाई स्कूल भवन एवं गौठान चारागाह बनाने हेतु अराक्षित उक्त शासकीय पट्टे की भूमि को निरस्त किये जाने हेतु आवेदन कलेक्टर महोदय दुर्ग को प्रेषित आवेदन पत्र श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रा. महो. के माध्यम से जांच हेतु प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16/06/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27/05/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

संपादकीय

सच कहा आगरकर ने, वैभव ने मजबूर कर दिया

किसी भी खेल में किसी खिलाड़ी को जल्दी देश की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिलता है। उसे कई स्तरों पर मैदान में साबित करना पड़ता है कि वह देश के लिए खेलने की योग्यता रखता है। कई लोग दस दस,बीस बीस साल खेलते रहते हैं और साबित नहीं कर पाते हैं कि वह देश के लिए खेलने की योग्यता रखते हैं और गिनती के खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो एक मौका मिलने पर साबित करने का प्रयास करते हैं कि वह गुड,बेटर,बेस्ट नहीं असाधारण खिलाड़ी हैं। हर खेल में गुड बहुत ज्यादा,बेटर उससे कम,बेस्ट उससे कम खिलाडी.होते हैं और असाधारण खिलाड़ी तो कभी कभी सामने आते हैं। असाधारण खिलाड़ी कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे देते हैं। उनको कुछ गेंद खेलने का मौका मिलता है तो वह बता देते हैं कि मैं असाधारण खिलाडी हूं। इस देश में अब तक क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ही साधारण परिवार में पैदा होने वाली असाधारण खिलाडी.माने जाते हैं, उनको ग़ॉड आफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है।

देश में सचिन तेंदुलकर के साथ किसी खिलाड़ी की तुलना अब तक नहीं की जाती है। बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी तो बहुत हैं लेकिन असाधारण कोई नहीं है ।तीन दशक से ज्यादा समय तक इस देश में तेंदुलकर जैसा एक भी खिलाड़ी नहीं हुआ। कोई सोचता भी नहीं था कि तेंदुलकर जैसा कोई खिलाड़ी हो भी सकता है ।आईपीएल 2026 में जाकर अब देश के लोग मानने लगे हैं कि देश में किक्रेट का एक और असाधारण खिलाडी है ।उसका नाम है वैभव सूयर्वंशी। अभी उसकी तुलना तेंदुलकर से नहीं की जा सकती लेकिन उसे असाधारण क्रिकेट खिलाड़ी तो माना जा रहा है खासकर आईपीएल में उसके खेल को देखकर, उसे मिले पांच अवार्ड को देखकर। 15 साल की उम्र में जब बच्चे बैट पकड़कर गेंद को मारना सीखते हैं तो वैभव ने 15 साल की उम्र में 59 छक्कों का रिकार्ड तोड़कर बता दिया कि वह असाधारण हैं। कोई खिलाड़ी आईपीएल में आज तक एक साथ पांच अवार्ड नहीं जीत पाया है, वैभव ने दूसरे सीजन में पांच अवार्ड जीतकर देश विदेश में चर्चा का विषय बने रहे हैं।

उनकी असाधारण खेल प्रतिभा को देखते हुए ही आईपीएल के दौरान ही उनको भारतीय टी-20 टीम में शामिल करने की बातें की जाने लगी थी। देश के जितने दिग्गज क्रिकेट खिलाडी हैं, सब चाहते हैं उनको भारतीय टीम में शामिल कर खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। सुनील गावस्कर व तेंदुलकर किसी क्रिकेट खिलाड़ी की तारीफ कम ही करते हैं ।उन्होंने भी जब कह दिया कि वैभव को भारतीय टी-20 टीम में मौका जल्द दिया जाना चाहिए तो साफ हो गया था कि जल्द ही उनको भारतीय टी-20 टीम में शामिल कर देश व विदेश में खेलने का मौका दिया जाएगा। आईपीएल समाप्त होने के कुछ ही दिनों के भीतर यह खबर भी आ गई कि वैभव को श्रीलंका जाने वाली ए टीम में मौका दिया गया है और साथ ही आयरलैंड व इंग्लैंड दौरे के लिए भी उनको चुना गया है। वह भारतीय टीम के लिए सबसे कम उम्र में चुने गए हैं। वह जब जिस दिन मैदान में उतरेंगे उस दिन वह सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में देश के लिए खेलने का रिकार्ड तोड़ेंगे और नया रिकार्ड बनाएंगे।

चीफ सलेक्टर अजीत आगरकर ने वैभव को टीम इंडिया के लिए चुने जाने के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वैभव सूयर्वंशी ने उनको टीम इंडिया के लिए चुनने को मजबूर कर दिया। यह सच है कि टीम इंडिया के लिए 15 साल के किसी खिलाड़ी को किसी तरह से योग्य नहीं माना जाता है। वैभव ने आईपीएल में खेल ही ऐसा खेला कि देश के लिए खिलाड़ी चुनने वाले अजीत आगरकर उनको चुनना पड़ा और कहना भी पड़ा कि वैभव ने अपने दो आईपीएल के खेल से हमको चुनने के लिए मजबूर कर दिया। यानी देश के लिए खेलने का मौका उनको देना पड़ा। ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो अपनी उम्र से ज्यादा अच्छा खेलते हैं,उनकी उम्र को देखते हुए जब लोग उसका खेल देखते हैं सबको हैरानी होती है कि ऐसा कैसे खेल लेता है। वैभव ने दिग्गज बैट्समैन हो या दिग्गज खिलाड़ी सबको हैरान किया है। सबने उसका तारीफ की है। सबने उसकी प्रतिभा की सराहना की है कि ऐसी प्रतिभा किसी किसी खिलाड़ी में होती है।

वैभव भारत ए टीम के साथ श्रीलंका पहुंच गए हैं और उनको श्रीलंका व अफगानिस्तान के साथ कई मैच खेलने हैं ।उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह आईपीएल की तरह की श्रीलंका में शानदार खेल का प्रदर्शन करेंगे। अब तक तो उनको जब भी मौका मिला है वह अच्छा खेले हैं, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि उनका श्रीलंका दौरा सफल रहेगा और वह देश के किक्रेट प्रेमियों को निराश नहीं करेंगे। क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है,इसलिए वैभव कुछ मैच अच्छा नहीं खेल पाए तो भी उनको आगे खेलने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह खुद को मैदान में साबित कर सकें। यह वक्त वैभव को मौका देने का है। मौका मिला है तो अच्छा खेलते हैं तो अच्छी बात है, एक दो मैच अच्छा नहीं खेलते हैं तो भी भरोसा करना होगा वह आगे देश के लिए अच्छा खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट को कई दशकों बाद असाधारण खिलाड़ी मिला है, उसका हर तरह से ख्याल क्रिकेट बोर्ड व क्रिकेट खिलाड़ियों का रखना होगा।

राजनीतिक रुझान में दिखे बदलाव के संकेत

के.एस. तोमर

हालिया स्थानीय निकाय चुनावों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति का मूड बदल दिया है। भाजपा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। नतीजों ने सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर कांग्रेस की खामियां उजागर की हैं। बेशक 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीति में सरगर्मी बढ़ेगी।

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगर निगम और जिला परिषद चुनावों ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी है। इन चुनाव परिणामों की शुरुआत में केवल स्थानीय निकायों तक सीमित माना जा रहा था। लेकिन परिणाम आने के बाद जाहिर हुआ कि जनता ने इन्हें सरकार के कार्य प्रदर्शन और राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा के रूप में देखा। भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक बढ़त ने सत्तासीन कांग्रेस सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष राजनीतिक चुनौतियां समय से पहले गहराती दिखाई देने लगी हैं।

राज्य कांग्रेस सरकार का कायर्काल अभी बाकी है लेकिन चुनावी परिणामों ने संकेत दिया कि जनता के एक वर्ग में धीरे-धीरे असंतोष पैदा हो रहा है। भाजपा ने इन नतीजों को सरकार के खिलाफ उभरते जनमत के रूप में पेश किया। यह संदेश देने की कोशिश की कि राज्य की राजनीतिक हवा बदलनी शुरू हो गई है।

जिला परिषद चुनावों के परिणाम भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बनकर उभरे। कुल 253 सीटों में से 143 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी ने स्पष्ट बढ़त हासिल की, जबकि कांग्रेस 59 सीटों तक सीमित रह गई। यह अंतर केवल चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। भाजपा अब दावा करने लगी है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांवों तक फैल रही है।

बिलासपुर में भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के गृह जिले में पार्टी ने जिला

परिषद की सभी सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया कर दिया। इस जीत ने नड्डा के प्रभाव को फिर दर्शाया है। राज्य में अब भविष्य की राजनीति को लेकर नई चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।

हमीरपुर के परिणामों ने भी कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा ने प्रभावी प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को करीब हाशिये पर पहुंचा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां सक्रिय रहे जो भाजपा का माहौल बनाने में मददगार रहा। सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस संगठन जमीनी स्तर पर अपेक्षित मजबूती नहीं दिखा सका।

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आक्रामक चुनावी अभियान के दौरान कई बड़ी गारंटियां दी थीं। महिलाओं, युवाओं, कमर्चारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर किए गए वादों ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब विपक्ष इन्हीं गारंटियों को सरकार की बड़ी राजनीतिक कमजोरी में बदलने की कोशिश कर रहा है।

भाजपा ने पूरे चुनाव प्रचार में यह नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया कि कांग्रेस अपने अधिकांश वादे पूरा करने में विफल रही। स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ बेरोजगारी, प्रशासनिक सुस्ती और विकास कार्यों में देरी जैसे विषयों को विपक्ष ने प्रभावी ढंग से उठाया। कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं और फैसलों का राजनीतिक लाभ जनता तक पहुंचाने में कमजोर दिखाई दी।

सरकार की ओर से कई कल्याणकारी कदमों की घोषणा जरूर हुई, लेकिन राजनीतिक संवाद की कमी के कारण उनका प्रभाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा। यही वजह रही कि भाजपा जनता में यह धारणा बनाने में सफल होती दिखी कि सरकार और लोगों के बीच दूरी बढ़ रही है।

साल 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा संगठन में निराशा का माहौल था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों ने पार्टी को नई ऊर्जा दे दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनावी रणनीति को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखा। भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति के बजाय प्रशासनिक कमजोरी, अधूरी घोषणाओं और जन असंतोष को हथियार बनाया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बूथ स्तर के नेटवर्क ने भी भाजपा की चुनावी तैयारी को मजबूती दी। पार्टी अब यह मानने लगी है कि यदि यही राजनीतिक माहौल बना रहा तो सत्ता विरोधी भावना 2027 से पहले ही अधिक तीव्र हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भाजपा अभी भी राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी मान रही है।

मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए यह स्थिति केवल राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि प्रशासनिक परीक्षा भी बनती जा रही है। यदि कांग्रेस इन नतीजों को केवल स्थानीय चुनावों तक सीमित मानकर नजरअंदाज करती है, तो सरकार और जनता के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो सकती है। कांग्रेस नेतृत्व को अब तेजी से संगठनात्मक तालमेल मजबूत करना होगा। साथ ही चुनावी गारंटियों के क्रियान्वयन, युवाओं के बीच भरोसा बहाल करने और मध्य वर्ग की नाराजगी कम करने की दिशा में प्रभावी राजनीतिक संदेश देना होगा। आने वाले महीनों में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह प्रशासनिक फैसलों को राजनीतिक समर्थन में कैसे बदले।

2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय चुनावों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति का मूड बदल दिया है। भाजपा आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राज्य की राजनीति आने वाले समय में और अधिक तीखी तथा प्रतिस्पर्धी होने के संकेत दे रही है।

धनी तबकों पर ले जाए

प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की करनी से पैदा हुई समस्या का मुकाबला करने की सारी जिम्मेदारी नागरिकों पर डालने का प्रयास किया है। मगर उससे हालात नहीं सुधरेंगे। बेहतर होगा वे अपना धनी तबकों पर ले जाएं।

आर्थिक संकट के बारे में प्रधानमंत्री के भाषणों से देश में फैले भय के बीच अब केंद्र ने सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के आयात पर शुल्क बढ़ा कर 15 (10 प्रतिशत कस्टम+ 5 फीसदी कृषि एवं विकास उपकर) कर दिया है। गौरतलब है कि सोने का आयात विदेशी मुद्रा भंडार में सेंध लगने का बड़ा कारण बना रहा है। मगर कारणों की पड़ताल करें, तो आयात बढ़ने की सीधी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार पर जाएगी।

केंद्र ने मई 2022 में यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर अमल शुरू किया, जिसके तहत वहां से टैरिफ रेट कोटा सिस्टम के तहत स्वर्ण आयात पर शुल्क सामान्य छह प्रतिशत से एक प्रतिशत कम (यानी पांच प्रतिशत) कर दिया गया। इसके पहले (2022 में) भारत के कुल स्वर्ण आयात में यूएई का हिस्सा 7.9 प्रतिशत (2.9 बिलियन डॉलर) था, जो पिछले साल 28 प्रतिशत (16.5 बिलियन डॉलर) हो गया। इस बीच पिछले साल सोने के भाव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। इससे सोना आम मध्य वर्ग की पहुंच से बाहर हो गया। जबकि अति धनी लोग खरीदारी करते रहे, जिससे डॉलर बाहर गया। प्रधानमंत्री ने मध्य वर्ग से विदेश जाने से बचने का आह्वान भी किया है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या में पिछले दो साल में गिरावट आई है।

फिर भी डॉलर बाहर जाने में बढ़ोतरी हुई, तो उसका कारण अति धनी व्यक्तियों का विदेश में चल और अचल संपत्ति में निवेश है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक 26.4 बिलियन डॉलर का निवेश इन लोगों ने विदेश में किया। ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटैंस स्कीम, टैक्स राहत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आदि के नाम पर विदेशी कर्मियों के लिए खुद इसका मार्ग प्रशस्त किया।

ये मुद्दे इसलिए उठे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की करनी से पैदा हुई समस्या का मुकाबला करने की सारी जिम्मेदारी नागरिकों पर डालने का प्रयास किया है। मगर उससे हालात नहीं सुधरेंगे। बेहतर होगा सरकार संकट-कालीन प्रशासनिक उपाय करे और अपना ध्यान मध्य वर्ग के बजाय धनी तबकों पर ले जाए।

हिंडन की दुर्दशा : नदी जल में प्रदूषण से बढ़ते स्वास्थ्य खतरे

पंकज चतुर्वेदी

हिंडन नदी का प्रदूषण गंभीर होने के बावजूद ठोस सरकारी प्रयास नहीं हो रहे। एनजीटी ने बार-बार आदेश दिये लेकिन अनुपचारित सीवेज जारी है, जिससे पानी जहरीला हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों व दिल्ली में गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) हर बार गुस्सा दिखाता है लेकिन सरकारी मशीनरी कुछ वादे करती है, कुछ दावेझ लेकिन इससे तो हिंडन के हालात सुधरने से रहे। दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिंडन व उनकी सहेली कृष्ण और काली नदियों के हालात अब इतने खराब हो गए हैं कि उससे राजधानी दिल्ली के लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। पश्चिमी उ .प्रर . के ग्रामीण अंचलों में नदियों ने भूजल भी गहरे तक जहर बना दिया है। अक्तूबर, 2016 में ही एनजीटी ने नदी के किनारे के हजारों हैंडपंप बंद कर गांवों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था का आदेश दिया था। हैंडपंप तो कुछ बंद भी हुए लेकिन विकल्प न मिलने से मजबूर ग्रामीण वही जहर पी रहे हैं। एनजीटी ने यह भी मान लिया है कि पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए धरातल पर कुछ काम हुआ ही नहीं।

हिंडन नदी भले ही उत्तर प्रदेश में बहती हो और उसके जहरीले जल ने तट पर बसे गांवों में तबाही मचा रखी हो , लेकिन अब दिल्ली भी इसके प्रकोप से अछूती नहीं। ज्ञात हो अगस्त, 2018 में एनजीटी के सामने बागपत जिले के गांगनोली गांव के बारे एक अध्ययन पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि गांव में अभी तक 71 लोग कैंसर के कारण मर चुके हैं और 47 अन्य चपेट में हैं वहीं हजार से अधिक लोगों को पेट के गंभीर रोग हैं और इसका मुख्य कारण हिंडन का जहर है। इस पर एनजीटी ने विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट फरवरी 2019 पेश की गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि हिंडन व उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के लिए मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जिम्मेदार हैं। एनजीटी ने तब आदेश दिया कि सुनिश्चित किया जाए कि हिंडन का जल कम से कम नहाने काबिल तो हो। मार्च, 2019 में कहा गया कि इसके लिए एक ठोस काययोजना छह महीने में प्रस्तुत हो। समय सीमा निकले तीन साल बीत गए, बात कागजों से आगे बढ़ी ही नहीं। गौरतलब है कि हिंडन का जहर अब दिल्ली के लिए भी काल बन रहा है। गंगा-यमुना के दोआब की भूमि से ही दिल्ली की विशाल आबादी की फल-सब्जी, अनाज की जरूरतें पूरी होती हैं। सिंचाई में इस्तेमाल हिंडन के जहरीले जल से खाद्य पदार्थों के जरिये दिल्ली वालों तक कई बीमारियां पहुंच रही हैं ।

ऐसी कई रिपोर्ट सरकारी बस्तों में बंद है, जिसमें कहा गया है कि हिंडन के पानी को जहरीले रसायनों का मिश्रण कहना बेहतर होगा। पानी में आक्सीजन शून्य है व कोई जीव-जंतु बचा नहीं है। यदि पानी में हाथ डुबो दें तो त्वचा रोग हो सकता है और यदि आप इसे पीते हैं तो हेपेटाइटिस या कैंसर जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। हिंडन को सीवर से रिवर बनाने के लिए भले ही एनजीटी खूब आदेश दे लेकिन नीति-निर्माताओं को हिंडन की मूल समस्याओं को समझना होगा। इसके नैसर्गिक मार्ग को बदलना, इसमें शहरी व औद्योगिक नालों का मिलना, इसके जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण—इन तीनों पर एक साथ काम किए बगैर नदी का बचना मुश्किल है।

दिक्कत यह भी, कुछ कारखानों का बचाव कर रही सरकार मानने को तैयार नहीं कि हिंडन का पानी जहर से बदतर है। कुछ साल पहले देश की नदियों में प्रदूषण की जांच में जुटे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हिंडन नदी के पानी को नहाने लायक भी नहीं पाया है। बोर्ड ने यह जानकारी एनजीटी के तत्कालीन प्रमुख स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपे हलफनामे में दी थी। सीपीसीबी ने प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद में नदी के पानी की जांच की। हलफनामे में बताया कि नदी का पानी पर्यावरण अधिनियम, 1986 के तहत तय नहाने के पानी के मानकों के अनुरूप नहीं है। इसके समाधान के लिए बोर्ड ने ठोस अवशिष्ट को नदी किनारे और नदी में न फेंकने की हिदायत दी है। इसके अलावा बोर्ड ने कहा है कि अशोधित कचरा नदी में न फेंका जाए बल्कि नगरपालिका अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के तहत इसकी सही व्यवस्था की जाए। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंडन के पानी को जहरीला बताए जाने के सीपीसीबी के दावे को झुठला दिया था।

हिंडन जहां भी शहरी क्षेत्रों से गुजर रही है, इसके जल-ग्रहण क्षेत्र में बहुमंजिला आवास बना दिए गए और इन कालोनियों के अपशिष्ट भी इसी में जाते हैं। नए पुल, मेट्रो आदि के निर्माण में हिंडन को सुखा कर वहां कंक्रीट उगाने में हर कानून को कुचला जाता रहा। आज भी गाजियाबाद जिले में हिंडन के तट पर कूड़ा फेंकने, मलबा या गंदा पानी डालने से किसी को भय-संकोच नहीं। अब नदी के जहर का दायरा विस्तारित होता जा रहा है।

जंगलों से जननी सुरक्षा तक: सुरक्षित मातृत्व की राह पर बदलता छत्तीसगढ़

जगत प्रकाश नड्डा

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक पैमाना उसकी सड़कों, भवनों और उद्योगों से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से तय होता है जो अपने सबसे संवेदनशील नागरिकों की रक्षा करती है। गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होते हैं। जब एक मां सुरक्षित रहती है तो केवल एक जीवन नहीं बचता, बल्कि एक पूरे परिवार, समाज और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भारत ने पिछले एक दशक में मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस परिवर्तनकारी यात्रा को तय किया है, वह विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में उभरी है। इस परिवर्तन के केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) है, जिसने गर्भवती महिलाओं तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है। इस अभियान की सफलता की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक छत्तीसगढ़ की है, जहां घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और दूरस्थ आदिवासी अंचलों के बीच मातृ स्वास्थ्य सेवाओं ने नई पहचान बनाई है।

दस वर्ष पहले जिन क्षेत्रों में गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच की कल्पना भी कठिन थी, वहां आज हर महीने की 9 तारीख मातृ स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सकीय सेवाओं का प्रतीक बन चुकी है। यह बदलाव केवल योजनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, तकनीकी नवाचार, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और जन-भागीदारी के सामूहिक प्रयासों की कहानी है।

नौ तारीख बनी सुरक्षित मातृत्व का प्रतीक

9 जून 2016 को शुरू हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की अवधारणा सरल लेकिन प्रभावशाली थी। गर्भावस्था के नौ महीनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माह की नौ तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रसव पूर्व जांच दिवस के रूप में निर्धारित किया गया। इस दिन सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच, परामर्श और आवश्यक परीक्षणों की व्यवस्था की जाती है। इस पहल ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को नियमितता और पहचान दी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और उनके परिवारों के लिए यह समझना आसान हुआ कि प्रत्येक माह की नौ तारीख स्वास्थ्य जांच के लिए निर्धारित है। परिणामस्वरूप प्रसव पूर्व जांच की पहुंच और स्वीकायर्ता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

आज देशभर में करोड़ों महिलाओं ने इस अभियान का लाभ उठाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान समय पर जांच और जोखिमों की पहचान ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती थी भूगोल, समाधान बना समुदाय

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां देश के अनेक राज्यों से भिन्न हैं। बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जैसे जिलों के बड़े हिस्से वनाच्छादित हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां बरसात के मौसम में पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। वर्षों तक इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहा। आदिवासी अंचलों में पारंपरिक मान्यताओं और घरेलू प्रसव की प्रथा भी लंबे समय तक मातृ स्वास्थ्य सुधार की राह में बाधा बनी रही। कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी प्रकार की चिकित्सकीय जांच नहीं कराती थीं। जटिलता होने पर अस्पताल पहुंचने में देर हो जाती थी और कई बार स्थिति गंभीर हो जाती थी।

यहीं से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने बदलाव की शुरुआत की। राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संयुक्त रूप से रणनीति तैयार की कि जोखिम सामने आने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले उसकी पहचान की जाए। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, हाट-बाजार क्लीनिक, विशेष स्वास्थ्य शिविर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाओं को गांवों तक पहुंचाया गया। आज स्थिति यह है कि जिन क्षेत्रों में कभी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सीमित थी, वहां गर्भवती महिलाओं का नियमित पंजीकरण, जांच और फॉलोअप संभव हो रहा है।

समय रहते जोखिम की पहचान बनी सबसे बड़ी ताकत

मातृ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश गंभीर प्रसूति जटिलताएं अचानक नहीं होतीं। उनके संकेत गर्भावस्था के दौरान दिखाई देने लगते हैं। यदि समय पर पहचान हो जाए तो अधिकांश जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान है। गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, गभर्कालीन मधुमेह, पूर्व प्रसव संबंधी जटिलताएं, कम उम्र या अधिक उम्र में गभर्धारण तथा जुड़वा गर्भ जैसी स्थितियों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई है। इन मामलों को चिन्हित करने के बाद उन्हें उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों से जोड़ा जाता है ताकि प्रसव के समय किसी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न न हो। यही कारण है कि राज्य के दूरस्थ जिलों में भी जटिल प्रसवों के सुरक्षित प्रबंधन की संभावना बढ़ी है। चिकित्सकों के अनुसार, समय पर रेफरल और नियमित निगरानी ने अनेक माताओं और नवजातों का जीवन बचाया है।

डिजिटल ट्रैकिंग ने स्वास्थ्य सेवाओं को दिया नया आयाम

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक ने मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों को नई गति प्रदान की है। पीएमएसएमए पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नाम आधारित ट्रैकिंग संभव हुई है। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जांच के बाद जानकारी तत्काल ऑनलाइन दर्ज की जाती है। यदि किसी महिला को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा जाता है तो उसकी जानकारी संबंधित चिकित्सकीय इकाइयों तक पहुंच जाती है। इससे स्वास्थ्य तंत्र को पहले से तैयारी करने का अवसर मिलता है। प्रसव की संभावित तिथि, चिकित्सकीय स्थिति और आवश्यक सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध रहने से आपातकालीन परिस्थितियों का बेहतर प्रबंधन संभव हो पाता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां दूरी और परिवहन लंबे समय तक बड़ी चुनौती रहे हैं, डिजिटल निगरानी प्रणाली ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया है।

गांव की पगडंडी से अस्पताल तक, आशा कार्यकर्ताओं का असाधारण योगदान

यदि इस परिवर्तन की असली कहानी लिखी जाए तो उसमें सबसे प्रमुख स्थान अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का होगा। आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी इस पूरे अभियान की रीढ़ हैं। आशा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करती हैं, उन्हें नियमित जांच के लिए प्रेरित करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। कई दूरस्थ गांवों में उन्होंने सामाजिक मान्यताओं को बदलने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण संबंधी निगरानी करती हैं, जबकि एएनएम टीकाकरण, प्राथमिक जांच और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रारंभिक स्तर पर जोखिमों की पहचान कर विशेषज्ञ चिकित्सकों से समन्वय स्थापित करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता के बिना मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार की कल्पना संभव नहीं थी।

जब योजनाएं साथ आईं तो बना सुरक्षा का व्यापक कवच

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की सफलता केवल एक योजना की उपलब्धि नहीं है। इसकी प्रभावशीलता विभिन्न स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समन्वय से बढ़ी है। जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालों में प्रसव, दवाइयों, जांचों और परिवहन को निःशुल्क उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है, जबकि आयुष्मान भारत गंभीर मामलों में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इन सभी योजनाओं ने मिलकर गर्भवती महिलाओं के लिए एक ऐसा सुरक्षा तंत्र तैयार किया है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर आर्थिक सहायता और पोषण तक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

बस्तर की कहानी, जहां अस्पताल अब भरोसे का नाम है

बस्तर संभाग के कई गांवों में आज भी ऐसे परिवार मिल जाते हैं जो कुछ वर्ष पहले तक अस्पताल में प्रसव कराने से हिचकते थे। लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां बदली हैं। सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे जिलों में नियमित स्वास्थ्य शिविरों और सामुदायिक संवाद कार्यक्रमों ने विश्वास का वातावरण बनाया। जिन महिलाओं को पहले अस्पताल जाने में संकोच होता था, वे अब गर्भावस्था की शुरुआत से ही स्वास्थ्य जांच करा रही हैं।

कई मामलों में समय पर जांच के दौरान गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप या भ्रूण की असामान्य स्थिति की पहचान हुई और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सका। ऐसी हजारों कहानियां आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सुनाई देती हैं जहां मातृत्व अब भय नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा से जुड़ा अनुभव बन रहा है।

अगले दशक की दिशा : शून्य रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु का लक्ष्य

मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। दूरस्थ क्षेत्रों तक वर्षभर निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना, प्रसवोत्तर देखभाल को और मजबूत बनाना तथा शहरी गरीब बस्तियों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना अभी भी प्राथमिकताएं हैं। ड्रोन आधारित आपूर्ति प्रणाली, टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और प्रशिक्षित मिडवाइफरी सेवाओं का विस्तार आने वाले वर्षों में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और मजबूत बना सकता है।

छत्तीसगढ़ ने यह सिद्ध किया है कि कठिन भूगोल और सीमित संसाधनों के बावजूद यदि नीति, तकनीक और सामुदायिक भागीदारी एक साथ काम करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन संभव है। आज जब हर महीने की 9 तारीख को राज्य के हजारों स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाएं जांच के लिए पहुंचती हैं, तो यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। बस्तर के जंगलों से लेकर सरगुजा की पहाड़ियों तक फैलती यह नई स्वास्थ्य चेतना वास्तव में विकसित भारत और सशक्त छत्तीसगढ़ की आधारशिला बन रही है।

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं)

पढ़ाई के साथ-साथ कनाडा में करें पार्ट टाइम जॉब

कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए पढ़ने के साथ ही पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आप ये जॉब्स जरुर कर सकते है। भारतीय छात्रों के लिए कनाडा में जॉब करना बेहद पॉपुलर है। इन जॉब्स की मदद से आप रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर सकते हैं।

अब्रॉड में पढ़ने की चाह कई लोग रखते हैं। ऐसे में कनाडा भारतीय छात्रों के लिए स्टाडी करने के लिए काफी पॉपुलर है। भारत के लाखों छात्र इस समय कनाडा में पढाई कर रहे हैं। कनाडा पढ़ाई के मामले मे बहुत ही खर्चा आता है। यहां महीने का खर्च के लगभग 1 लाख रुपये तक होता है। इसी कारण भारतीय छात्र यहां पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि खर्चा निकल सके। आइए जानते है कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, जिन्हें करने से आपको लाखों रुपये तक सैलरी मिल सकती है।

एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क

एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की जॉब में ऑफिस से जुड़े काम देखते हैं, जैसे कि रिपोर्ट बनाना, बयान तैयार करना, फोन कॉल या दस्तावेज तैयार करना। गौरतलब है कि यहां पर क्लर्क के तौर पर काम करना काफी आसान है। हर घंटे काम करने से सिर्फ आपको 22.50 डॉलर मिलेंगे (1367 रुपये) मिलेंगे।

टीचिंग असिस्टेंट

पढ़ाई के साथ-साथ अगर आप भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करना बेहद आसान होता है। आपको इस प्रकार की नौकरी कैंपस के भीतर ही मिल जाती है और इसके लिए सिर्फ स्टूडेंट्स की भर्ती होती है। टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर छात्रों को प्रोफेसर्स की रिसर्च जैसी चीजों में मदद करती है। इस पार्ट टाइम नौकरी में हर घंटे 25.48 डॉलर (1550 रुपये) दिए जाते हैं। इस तरह एक महीने में 1798 डॉलर (1.09 लाख रुपये) कमाएं जा सकते है।

ट्रांसलेटर

अगर आप भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो उनके लिए ट्रांसलेटर की नौकरियां सबसे ठीक है। ट्रांसलेटर के तौर पर काम करना

काफी फायदे का सौदा हो सकता है। ट्रांसलेटर की नौकरी के लिए हर घंटे 30.77 डॉलर मिलते हैं। अगर आप कोई छात्र एक महीने में 80 घंटे ट्रांसलेटर की जॉब करता है। तो वह 2461 डॉलर (1.49 लाख रुपये) कमा सकते है।

फ्रीलांसर

यदि आप कनाडा में फ्रीलांसर के तौर पर कार्य कर सकते है। ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेट राइटर, डिजिटल मार्केटिंग जैसे काम फ्रीलांसर के तौर पर आराम से कर सकते हैं। फ्रीलांसर तौर पर जॉब करने पर 23.51 डॉलर (1428 रुपये) कमाते हैं। एक महीने में 1880 डॉलर की कमाई की जा सकती है। भारतीय रुपये में बात करें तो आप महीने में 1.14 लाख रुपये कमा सकते हैं।

शानदार कॅरियर बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, मिलेगी मनचाही सफलता

अगर आप भी अपने कॅरियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे।

हम सभी का सपना होता है कि हमारा कॅरियर अच्छा होता है। हालांकि इसके लिए अलग-अलग फैक्टर काम करते हैं। सिर्फ अकेले पढ़ाई से ही काम नहीं चल पाता है। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वहीं आपको उन सभी सवालों के जवाब अच्छे से आते हैं, तो आपको नौकरी मिलने में दिक्कत नहीं आती है। वहीं अगर आपको उन सवालों के जवाब नहीं आते हैं, तो जॉब आपके हाथ से चली जाएगी। ऐसे में अगर आप भी अपने कॅरियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे।

बता दें कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है, जो फील्ड में काम आती है। फिर चाहे वह पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। दोनों की हालातों में कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास योग्यता के साथ-साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है।

इसलिए पढ़ाई के अलावा अलग-अलग एक्टिविटी का भी हिस्सा बनें। जिससे आपका कॉन्फिडेंस स्किल्स बढ़ता जाए। हालांकि यह हम सभी लोग जानते हैं कि कॅरियर बनाने में हमेशा नई-नई टेक्नोलॉजी की मांग होती रहती है। नई तकनीक पुरानी होने से पहले आपको उसके बारे में पूरी तरह से जान लेना चाहिए। साथ ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि आप जितनी ज्यादा जानकारी रखेंगे, उतना ही आपके कॅरियर को फायदा मिलेगा।

कई लोग कॅरियर बनाने के कारण अपने परिवार से दूर होते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें तनाव मुक्त होकर और खुश रहकर कॅरियर बनाने का प्रयास करना चाहिए।

नौकरी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आपका कॉन्टैक्ट में बने रहना चाहिए। जिससे आपको समय-समय पर कई तरह की जानकारी और कॅरियर बनाने के लिए अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलती रहती है। इसलिए अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाएं और लोगों से कॅरियर से संबंधित जानकारियां एकत्र करते रहें।

कॅरियर के मार्केट में खुद को कीमती समझें और पैसे से बिकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अपने काम और टैलेंट पर भरोसा रखें और समय-समय पर अपनी योग्यताओं को लगातार डेवलप करते रहना चाहिए।

अगर आपके पास 40 लाख तक का बजट है, तो आप भारत में सीट मिलने का इंतजार करने के बजाय विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस सीट बुक कर सकते हैं। क्योंकि विदेश की यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के बाद पूरा प्रोसेस होने में 2-3 सप्ताह का समय लग जाता है।

विदेश में एमबीबीएस करने से पहले करें बजट प्लानिंग

जागरुकता की कमी के चलते लाखों की संख्या में ऐसे नीट अभ्यर्थी होते हैं, जो 500 या इससे कम स्कोर लाते हैं। इसके बाद भी वह काउंसिलिंग के लास्ट राउंड तक सीट मिलने का वेट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 40 लाख तक का बजट है, तो आप भारत में सीट मिलने का इंतजार करने के बजाय विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस सीट बुक कर सकते हैं। क्योंकि विदेश की यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के बाद पूरा प्रोसेस होने में करीब 2-3 सप्ताह का समय लग जाता है। ऐसे में आप बिना देर किए बेहतर विदेशी यूनिवर्सिटी चुनकर एमबीबीएस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको विदेश से एमबीबीएस करने में लगने वाले बजट के बारे में बताने जा रहे हैं।

कैसे करें विदेशी यूनिवर्सिटी का चुनाव

ट्यूशन फीस - 5 साल के लिए
एक साल बाद - वापसी के लिए टिकट
विदेश में रहने का खर्च
भोजन का खर्च
कपड़े या अन्य जरूरी एसेसरीज का खर्च

यदि आप रूस, चीन, कजाकिस्ता, जॉर्जिया, नेपाल, इजिप्ट और बांग्लादेश जैसे देशों से एमबीबीएस करने पर आपकी पढ़ाई से लेकर रहने, खाने और अन्य चीजों को मिलाकर कुल खर्च 25 से 30 लाख के बीच होगा।

मेडिकल सीट्स

इन देशों की तमाम यूनिवर्सिटी में करीब 16,000 मेडिकल सीट्स हैं। हर विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस अलग हो सकती है। ऐसे में स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए एनएमसी के दिशा-निर्देशों को अच्छे से पढ़ व समझ लें। क्योंकि ये कार्यक्रम 54 महीने की अवधि के गैर-अनुपालन की वजह से भारत में मान्य नहीं हैं। आपका MBBS NMC निर्देशानुसार कम से कम 60 महीने का होना चाहिए।

ऐसे शॉर्टलिस्ट करें यूनिवर्सिटी

विदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप पिछले 3 सालों की कटऑफ और विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस आदि देख सकते हैं। इसके साथ ही भारत के प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी आदि की भी फीस देख सकते हैं। फिर आप अपने बजट, रैंक और ग्रेड के हिसाब से यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं।

यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस का ऐसे करें भुगतान

फीस का भुगतान सीधे यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में करना चाहिए। विदेश से एमबीबीएस करने के लिए किसी एजेंट का सहारा न लें। क्योंकि इससे आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। आपकी फीस, हॉस्टल और आगमन का शुल्क बंटा होना चाहिए। अन्य सेवाओं के लिए उस देश में पहुंचने के बाद भुगतान करें। वहीं यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट आपको मिलता है। ऐसे में फीस सीधे उसी अकाउंट में भेजे।

बता दें कि रूस में 2 तरीकों से वार्षिक ट्यूशन फीस विश्वविद्यालय 2 पार्टी और 3 पार्टी अनुबंधों के तहत ली जाती है। 2 पार्टी अनुबंध के तहत यूनिवर्सिटी प्रवेश पत्र के मुताबिक ट्यूशन फीस अपने अकाउंट में जमा करवाता है। वहीं 3 पार्टी अनुबंध के तहत यूनिवर्सिटी एजेंट के जरिए ट्यूशन फीस वसूलती है।

पहले साल का बजट

ऐसे में अगर आप भी विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं, तो पहले साल के खर्चों का बजट जैसे छात्रावास खर्च, आगमन के बाद की सेवाएं, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट, वीजा, भारतीय भोजन पैकेज (अगर कोई हो), परामर्श शुल्क कोचिंग आदि तैयार रखें। पहले साल में आपका खर्च 8-10 लाख के बीच आता है। वहीं अगर कोई स्टूडेंट जॉर्जिया से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, तो पहले साल में 10-12 लाख रुपए की जरूरत होगी।

जरूरी टिप्स

- विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने से पहले अपना बजट योजना अच्छे से तैयार कर लें। वहीं अकादमिक सत्र शुरू होने के पहले अप्लाई करें।
- रूस और जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी में अक्तूबर महीने में आवेदन हो जाना चाहिए। वरना अगले साल के एमबीबीएस सीट दाखिला सत्र के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- एजेंट द्वारा एमबीबीएस सीट बुक करने के दौरान कभी भी 3 पार्टी समझौते पर हस्ताक्षर न करें। बल्कि सीधे यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में फीस जमा करें।
- विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जल्दी सीटें बुक हो जाती हैं, इसलिए आवेदन में देरी न करें।

पायलट बन चमकाएं कॅरियर

वर्तमान समय में एविएशन इंडस्ट्री में तेजी से ग्रोथ हो रही है। साथ ही इस फील्ड में अवसरों की भरमार है। ऐसे में आप इस फील्ड में कॅरियर बनाकर अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं।

अक्सर आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर लोगों के मन में आसमान मापने का सपना होता है। अधिकतर लोग पायलट बनकर आसमान में ऊंची उड़ान भरने का सपना देखते हैं। हालांकि आज के समय में कॅरियर के लिहाज से युवाओं के पास कई तरह के ऑप्शन होते हैं। जिसमें वह डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं कई युवा ऐसे में हैं, जो पायलट बनने का ख्वाब देखते हैं। अगर आपका लक्ष्य क्लियर होता है, तो आपको सिर्फ इस ओर बढ़ने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप भी पायलट बनकर अपना भविष्य चमकाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस फील्ड में बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वर्तमान समय में एविएशन इंडस्ट्री में तेजी से ग्रोथ हो रही है। साथ ही इस फील्ड में अवसरों की भरमार है।

ऐसे करें पायलट बनने की तैयारी

पायलट बनने के लिए आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्य के साथ कम से कम 50 फीसदी अंको से पास होना चाहिए। जिसके बाद आपको किसी एविएशन संस्थान में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। फिर आपको इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट में पास होना होता है। सभी प्रोसेस में सफल होने के बाद संस्थान में एडमिशन मिलता है। जहां पर आपको प्लेन से जुड़ी बारीकियां सिखाने के साथ प्लेन उड़ाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी।

एयरफोर्स में बनें पायलट

अगर आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको 12वीं पास करने के बाद एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम एग्जाम और यूपीएससी एनडीए एग्जाम क्लियर करना होगा। जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देती है। वहीं इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम भी दे सकते हैं। हालांकि इस एग्जाम के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से 12वीं या फिर बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए।

कमर्शियल पायलट

बता दें कि 12वीं की पढ़ाई के बाद आप एविएशन संस्थान से ट्रेनिंग लेकर बतौर कॉमर्शियल पायलट अपना कॅरियर बना सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग पीरियड 18-24 महीने का होता है। फिर कमर्शियल पायलट के लिए आपको रिटेन एग्जाम और फिटनेस टेस्ट देना होता है। इन दोनों चीजों को क्लीयर करने के बाद आपको कमर्शियल पायलट बनने की योग्यता हासिल हो जाती है।

सोशल मीडिया सेंसेशन हैं पायल राजपूत

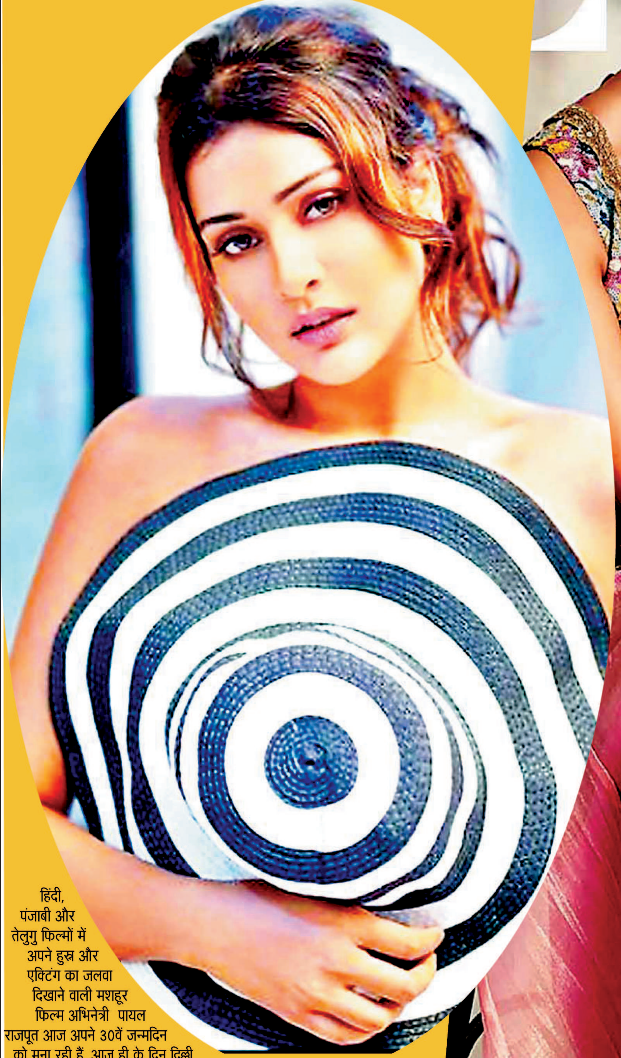

हिंदी, पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में अपने हुस्न और एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली मशहूर फिल्म अभिनेत्री पायल राजपूत आज अपने 30वें जन्मदिन को मना रही हैं. आज ही के दिन दिल्ली में साल 1992 में दिल्ली में जन्मीं पायल राजपूत आए दिन अपने लुक्स, स्टाइल और इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. पायल के आज बर्थडे के मौके पर आइए जानते है कि किस किस मौके पर एक्ट्रेस लाइमलाइट में आ चुकी हैं. पायल आए दिन इंस्टाग्राम पर आग लगाती रहती हैं. पायल अपने ही अंदाज में इंस्टाग्राम पर धमाल मचाती है. कभी वो बस तकिये के साथ फोटो शेयर कर देती है तो कभी अखबार के साथ और कभी अपनी किसी और अदा के साथ फोटो अपलोड करने में जरा सा भी परहेज नहीं करती हैं. एक्ट्रेस की इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनके 4 मिलियन फोलोअर्स हैं. पायल के फैंस को हमेशान उनके नए-नए फोटोज और वीडियोज का दिल से इंतजार रहता है. पायल राजपूतने अपने बेहतरीन फिल्मी करियर में वीरे दी वेडिंग , मिस्टर एंड मिसेज 420 रिटर्न, आरडीएक्स लव, आरएक्स 100 और डिस्को राजा जैसी हिंदी, पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में अपना जलवा दिखा चुकी हैं. फिल्मों के अलावा पायल सपनों से भरे नैना , ये है आशिकी, गुस्ताख दिल और प्यार तूने क्या किया जैसे कई टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं. फिल्मों और टीवी के साथ पायल मशहूर म्यूजिक एल्बम बादल बरसे में अपनी कातिलाना अदाओं से फैंस को घायल कर चुकी हैं. फिलहाल इन दिनों पायल अपने काम को लेकर काफी बिजी चल रही हैं।

41 की उम्र में दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट

सिंगापुर के बिजनेसमैन संग रचाएंगी शादी

41 की उम्र में दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट?टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक जेनिफर विंगेट अक्सर ही सुर्खियों में छाई रहती हैं फिर बात चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ की हो या फिर पर्सनल लाइफ की. बीते कुछ वक्त से जेनिफर विंगेट की शादी की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि करण सिंह ग्रोवर से तलाक के 12 साल बाद जेनिफर दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं. अब हाल ही में सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया कि जेनिफर विंगेट सिंगापुर के एक बिजनेसमैन संग रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही उनके साथ शादी करने वाली हैं.

हाल ही में शादी के डांस वाली एक रील पर कमेंट के बाद एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की शादी को लेकर अटकलें तेज हो गईं. बीते कुछ दिनों से जेनिफर विंगेट का नाम बिजनेसमैन विलियम इस्माइल के साथ जोड़ा जा रहा है. ये खबरें तब और भी ज्यादा हाइलाइट हो गईं जब एक्ट्रेस ने शादी से जुड़े कई सोशल मीडिया पेजों को फॉलो करना शुरू कर दिया. तबसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है. हालांकि, जेनिफर विंगेट की तरफ से शादी की इन खबरों पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

तलाक के 12 साल बाद दूसरी शादी

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेनिफर विंगेट इन दिनों विलियम इस्माइल को डेट कर रही हैं और दोनों की शादी भी होने वाली है. इसी रिपोर्ट में एक्ट्रेस के करीबी सोर्स के हवाले से दावा किया गया कि सिंगापुर में रहने वाले बिजनेसमैन इस्माइल, जेनिफर विंगेट के साथ रिलेशनशिप में हैं. जेनिफर और विलियम साथ में बहुत खुश हैं. विलियम ने छुट्टियों के दौरान जेनिफर को प्रपोज किया और उन्होंने हां कह दिया. अब वो अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं. जेनिफर वेंडर्स और वेडिंग सर्विसेज को शॉर्टलिस्ट कर रही हैं और उन्होंने शादी के लिए एक डिटेल्ड प्लान भी तैयार किया है.

क्रिश्चियन वेडिंग करेंगी जेनिफर

सोर्स की मानें तो शादी हिंदू रीति-रिवाज से नहीं, बल्कि ये एक क्रिश्चियन वेडिंग होगी. फिलहाल जेनिफर और इस्माइल सितंबर-अक्टूबर के आसपास शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और शायद दिसंबर-जनवरी का भी प्लान हो सकता है. फिलहाल कपल वेन्यू देख रहे हैं. उनके सभी करीबी दोस्तों को इन प्लान्स के बारे में पता है, जिनमें इंडस्ट्री के दोस्त जैसे हरलीन सेठी और जेनेलिया देशमुख भी शामिल हैं.

मलाइका अरोड़ा नहीं शिल्पा शेट्टी थी छैया छैया गाने के लिए पहली चॉइस

फराह खान कुंदर प्रतिष्ठित गीत - छैयां छैयां के बारे में बात करते हुए कहा कि आप छैयां छैयां गर्ल हैं. लेकिन सौभाग्य से आपके लिए कुछ पांच अभिनेत्रियों ने ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिया था. उन्होंने आगे कहा कि मलाइका कहीं भी राडार पर नहीं थीं. हमने शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, शिल्पा शिरोडकर और 2-3 अन्य लोगों से संपर्क किया था. एक को ट्रेन पर चढ़ने का फोबिया था, एक उपलब्ध नहीं थीं.

रिश्ते, ग्लैमर के साथ साथ बॉलीवुड की मशहूर डीवा मलाइका अरोड़ा ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ देखा है. अपने शानदार डांस मूव्स और होश उड़ा देने वाले आकर्षण से लाखों लोगों के दिलों को लुभाने वाली - ग्लैमरस और प्रेरणादायक आइकन मलाइका अरोड़ा डिज्नी+ हॉटस्टार के साथ बहुप्रतीक्षित डिजिटल डेब्यू कर रही हैं. तस्वीरें क्रेडिट मलाइका अरोड़ा इंस्टाग्राम वो हॉटस्टार स्पेशल्स के मूविंग इन विद मलाइका के एक नए, एक्सक्लूसिव शो में अनफिल्टर्ड बातचीत के माध्यम से प्रशंसकों को अपने जीवन तक पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार हैं. बहुप्रतीक्षित शो-मूविंग इन विद मलाइका के शुरुआती एपिसोड के साथ, निर्माता, निर्देशक, कोरियोग्राफर और एक खास दोस्त - फराह खान कुंदर दोस्ताना मुलाकात के लिए मलाइका के घर आईं. दोनों पुरानी यादों को ताजा करती हैं और मलाइका अरोड़ा के बनने की याद ताजा करती हुईं नजर आईं. दोनों ने उनके अतीत, वर्तमान और बहुत कुछ के बारे में बात की। इस बातचीत में, फराह खान कुंदर प्रतिष्ठित गीत - छैयां छैयां के बारे में बात करते हुए कहा कि आप छैयां छैयां गर्ल हैं. लेकिन सौभाग्य से आपके लिए कुछ पांच अभिनेत्रियों ने ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिया था.

उन्होंने आगे कहा कि मलाइका कहीं भी राडार पर नहीं थीं. हमने शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, शिल्पा शिरोडकर और 2-3 अन्य लोगों से संपर्क किया था. एक को ट्रेन पर चढ़ने का फोबिया था, एक उपलब्ध नहीं थीं.

फराह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि फिर मेकअप करने वाले ने कहा, मलाइका बहुत अच्छी डांसर हैं. जब वह ट्रेन पर चढ़ी तो हम पूरी तरह से उत्सुक थे कि वह इसे कर पाएगी या नहीं. लेकिन बाकी जैसा हम जानते हैं वह इतिहास है.

मय पर मिला खाद, नैनो उर्वरक से खेती की तैयारी हुई आसान–खेमलाल

जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग और सुगम वितरण व्यवस्था से किसानों को मिल रहा लाभ, आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे जिले के किसान

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

खरीफ सीजन की दस्तक के साथ खेतों में तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे समय में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराना खेती की सफलता का महत्वपूर्ण आधार होता है। राज्य सरकार के निर्देशों और जिला प्रशासन की सतत निगरानी से जिले की समितियों और वितरण केंद्रों में किसानों को सुगमता से खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और नैनो उर्वरकों के उपयोग की जानकारी देकर नई सोच के साथ खेती की ओर प्रेरित किया जा रहा है।

इसी व्यवस्था का लाभ ग्राम मानिकचौरी के किसान खेमलाल साहू को मिला। लगभग 4 एकड़ कृषि भूमि में खेती करने वाले खेमलाल खरीफ फसल की तैयारी के लिए धरमपुरा सोसायटी पहुंचे थे। यहां उन्हें बिना किसी परेशानी के आवश्यक खाद उपलब्ध हुआ। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग, मात्रा और उसके लाभों की जानकारी भी दी।

खेमलाल साहू बताते हैं कि पहले पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियां खरीदना और उन्हें खेत तक पहुंचाना काफी कठिन होता था। कई बार अधिक लागत और परिवहन की परेशानी के साथ पीक सीजन में उपलब्धता की चिंता भी बनी रहती थी। लेकिन इस बार उन्हें एक नया विकल्प मिला।

खेमलाल ने कहा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में जानकारी मिलने के बाद वे पहली बार इसका उपयोग करेंगे। छोटी शीशी होने से इसे ले जाना आसान है, लागत कम लगती है और समय पर उपलब्धता भी बनी रहती है। इससे खेती की तैयारी पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक महसूस हो रही है। जिले में खाद वितरण की सुचारू व्यवस्था और नैनो उर्वरकों के प्रति बढ़ती जागरूकता खेती को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

जाति प्रमाण पत्र मुद्दे पर आज ज्ञापन सौंपेंगे कर्मचारी और सामाजिक संगठन

राजनांदगांव। जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार 10 जून को राजनांदगांव में विभिन्न कर्मचारी संगठनों, सामाजिक प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कार्यक्रम के तहत दोपहर 4 से 5 बजे के बीच जिला कार्यालय परिसर स्थित डॉ. बाबा साहब आंबेडकर प्रतिमा के सामने एकत्र होकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाएगा। आयोजकों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 10 जून 2025 को राज्य सरकार को भेजे गए पत्र के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की जाएगी। इस संबंध में राज्यपाल से आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह भी किया जाएगा। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संगठनों, प्रबुद्ध नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है।

खास खबर

नैनो यूरिया–डीएपी से बदली खेती की तस्वीर, किसान जनक देवांगन को कम लागत में मिला बेहतर उत्पादन

खैरागढ़। जिले के किसान अब आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। परंपरागत खेती की जगह नई तकनीकों और उन्नत कृषि उत्पादों का उपयोग किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसी कड़ी में ग्राम टिकरीपारा (गंडई) के प्रगतिशील किसान जनक देवांगन ने नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का उपयोग कर अपनी खेती में सकारात्मक बदलाव लाया है।

जनक देवांगन ने बताया कि वे पिछले एक वर्ष से अपनी लगभग 5 एकड़ कृषि भूमि में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप उन्हें बेहतर उत्पादन प्राप्त होने के साथ-साथ कृषि लागत में भी उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने बताया कि पहले वे पारंपरिक खेती के तहत रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करते थे, जिससे समय के साथ उत्पादन में कमी आने लगी और खेती की लागत लगातार बढ़ती गई।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के मार्गदर्शन में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसे अपनी फसलों में अपनाया। इसके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च कम हुआ और फसलों की वृद्धि तथा उत्पादन में भी सुधार देखने को मिला। श्री देवांगन के अनुसार नैनो यूरिया फसलों को आवश्यक पोषक तत्व सीधे उपलब्ध कराता है, जिससे पौधों का विकास बेहतर होता है और उपज की गुणवत्ता भी बढ़ती है।

श्री देवांगन ने बताया कि नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का छिड़काव करना बेहद आसान है। इसकी छोटी बोतलें खेत तक ले जाने और उपयोग करने में सुविधाजनक होती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से वे अपनी विभिन्न फसलों में इसका नियमित उपयोग कर रहे हैं और लगातार अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जिले के अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसी आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं, जिससे कृषि लागत में कमी लाकर अधिक उत्पादन एवं बेहतर आय प्राप्त की जा सके। किसान जनक देवांगन की यह सफलता जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन रही है और आधुनिक कृषि की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

रेत के अवैध उत्खनन के मामले में तीन ट्रैक्टर जब्त

राजनांदगांव। जिले में रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने तीन ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में अवैध रूप से रेत उत्खनन करते पाए गए वाहनों को जब्त कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज विभाग की टीम ने डोंगरगांव तहसील के ग्राम बरगांव क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 08 बीजी 4068, सीजी 08 एयू 5299 तथा सीजी 08 बीए 6067 द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। इसके बाद विभाग ने तीनों ट्रैक्टरों को जब्त कर थाना डोंगरगांव को सुपुर्द कर दिया। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित प्रकरणों में खान एवं खनिज अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है।

वनांचल क्षेत्र के बच्चों की नैसर्गिक क्षमता, प्रतिभा व आत्मविश्वास हो रहा अभिव्यक्त : डॉ. रमन सिंह

लक्ष्य बनाकर चलें और मेहनत और लगन से करें पढ़ाई

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह स्पीकर हाऊस राजनांदगांव में छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज यहां दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से आए वनांचल क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। ऐसे बच्चों को मंच में सुनकर यह महसूस होता है कि एक आत्मविश्वास कैसे जाग्रत होता है।

दूरस्थ वनाचंल क्षेत्रों में उनके अभिभावक तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य करते हैं। जहां सुविधाओं की कुछ कमी के बावजूद ये अपने परिश्रम से उत्कृष्ट अंक लेकर आते है और अध्ययन के क्षेत्र में शहर के बच्चों को चुनौती देते हैं तथा आगे बढ़ते हैं। जो उनकी नैसर्गिक क्षमता, प्रतिभा एवं आत्मविश्वास को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि लक्ष्य बनाकर चलें और मेहनत एवं लगन से पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि केवल डॉक्टर व इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेसर, वकील, शिक्षक एवं समाज के अन्य क्षेत्रों में सेवा करते हुए देश के विकास में अपना योगदान दें।

उन्होंने बताया कि वनवासी भाई-बहनों के तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान कंकड़ के चुभने से संक्रमण फैल जाता था। इससे बचाव के लिए चरण पादुका योजना लायी गई। जंगल में निवास करने वाले वनवासियों को चप्पल दिए गए। उन्होंने बताया कि प्रयास विद्यालय दंतेवाड़ा में प्रारंभ किया गया था एवं एजुकेशन हब के माध्यम से बड़ी संख्या में बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तेंदूपत्ता की दर में वृद्धि की गई है। प्रतिमानक दर 1000 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए की गई है। उन्होंने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सफलता के नए आयाम प्राप्त करें। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने बालिका नम्रता नेताम एवं प्रेरणा साहू को

निःसंकोच होकर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने के लिए हौसला बढ़ाया। बालिकाओं ने बताया कि वे डॉक्टर बनना चाहती हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं दें। विधानसभा अध्यक्ष ने हितेश को लकी क्वाईन दिया और अच्छे से मन लगाकर पढ़ने के लिए कहा।

महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि तेंदूपत्ता के लाभांश की राशि छात्रवृत्ति की राशि का सदुपयोग करते हुए बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। शासन की योजना अंतर्गत चरण पादुका, साड़ी वितरण, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, प्रयास आवासीय विद्यालय के माध्यम से वनवासियों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कार्य किया गया। वही बच्चों की शिक्षा के लिए भी कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जनमानस के जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ें और विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देकर देश सेवा का कार्य करें। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव ने कहा कि वनांचल क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देने के लिए छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत अच्छी पहल की गई है। जिससे शैक्षणिक कार्य में बच्चों को मदद मिल रही है। आर्थिक तौर पर कमजोर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के लिए यह राशि मददगार है।

वनमंडलाधिकारी आयुष जैन ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लघु वनोपज तेंदूपत्ता, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2026 के तेंदूपत्ता संग्रहण सत्र में जिले में कुल 16517.502 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है। संग्रहण कार्य में कुल 18412 संग्राहक परिवार भाग लिया। जिसके अंतर्गत संग्रहण पारिश्रामिक भुगतान योग्य 9 करोड़ 8 लाख 46 हजार 360 रूपए निर्धारित की गई है। तेन्दूपत्ता संग्रहकों को संग्रहण पारिश्रमिक के साथ-साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिसमें संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित है। जिला यूनियन राजनांदगांव अंतर्गत वर्ष 2025 में 448 छात्र-छात्राओं को 60 लाख 81 हजार रूपए का भुगतान किया गया है।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष सचिन बघेल, राजगामी संपदा न्यास की अध्यक्ष श्रीमती पूणिर्मा साहू, कोमल सिंह राजपूत, खूबचंद पारख, श्रीमती रेखा मेश्राम, कलेक्टर जितेन्द्र यादव, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, एसडीएम राजनांदगांव गौतम पाटिल, एसडीओपी वन विभाग योगेश साहू, डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, हितग्राही बच्चे एवं नागरिक उपस्थित थे।

महाविद्यालय व विद्यालयों में नवीन शिक्षा पद्धति समय की आवश्यकता–रवि सिन्हा

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा पार्षद रवि सिन्हा ने कहा है कि बदलते समय और तकनीकी प्रगति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू की जा रही नवीन शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कदम है।

रवि सिन्हा ने कहा कि नई शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें व्यावहारिक, तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर समझ, विश्लेषण, नवाचार एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बन सकें।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन शिक्षण, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तथा वर्चुअल लैब जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, सरल एवं रोचक बनी है। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के नए अवसर मिल रहे हैं।

रवि सिन्हा ने बताया कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप विषय चयन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं महाविद्यालयों में बहु विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं तथा रोजगार के नए अवसरों तक पहुंच बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि नवीन शिक्षा पद्धति में कौशल विकास, शोध, नवाचार, खेलकूद, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी समान महत्व दिया गया है। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। नई शिक्षा नीति शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला एवं रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

रवि सिन्हा ने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अपनाई जा रही यह नवीन शिक्षा पद्धति भारत को ज्ञान आधारित, आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से इस परिवर्तनकारी शिक्षा व्यवस्था को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

कलेक्टर ने दी आरबीसी 6-4 के तहत 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृत

खैरागढ़। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृती दी है। इसमें तहसील खैरागढ़ के ग्राम दामरी निवासी दिपेश बंजारे पिता अजय दास बंजारे उम्र 06 वर्ष की मृत्यु जहरीले सर्प के काटने के कारण, निकटतम वारिसान अजय दास बंजारे को आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वीकृत राशि का आहरण कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

अमराई और बरगद की ठंडी छांव में ग्रामीणों से संवाद–सीईओ अभिषेक अग्रवाल

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

एक साथ 82402 ग्रामीणों ने जाना 125 दिन रोजगार की पहल और जल संरक्षण का महत्व

जिले के सभी 471 ग्राम पंचायतो में रोजगार सह आवास दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से रोजगार प्राप्त कर रहे 82402 ग्रामीणों तक सीधे जानकारी पहुंचाई गई। 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना में 125 दिनों का रोजगार, गांव के विकास में भागीदारी, समय पर मजदूरी भुगतान एवं आजीविका के नए साधन सहित आवास निर्माण की जानकारी दी गई। जल संरक्षण के लिए सामूहिक योगदान पर व्यापक चर्चा की गई।

उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मजदूरों को रोजगार कबीरधाम जिले में लगातार प्रदान किया जा रहा है। वतर्मान में 82402 ग्रामीणो को 2463 निर्माण कार्यो में रोजगार मिल रहा हैं। जिसमे 248 प्रधानमंत्री आवास निर्माण में 4670 हितग्राहियों को भी रोजगार प्राप्त है। ज्ञात हो की मनरेगा कार्य स्थल में रोजगार सह आवास दिवस में एक साथ एक ही दिन इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों को उनके अधिकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर जागरूक किया जाता है।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की मांग पर 2463 कार्य चल रहे हैं। कबीरधाम जिला सर्वाधिक मानव दिवस एवं सर्वाधिक ग्रामीणों को रोजगार देने के मामले में लगातार प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। रोजगार दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को बताया गया कि इस वर्षा ऋतु किस प्रकार वे अपने घरों में सोख्ता गड्ढा बनाकर जल संरक्षण कर सकते हैं। भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए सभी संभावित प्रयासों पर जानकारी देखकर जल संरक्षण करने के महा अभियान से जुड़ने आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री आवास में चल रहे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए ग्रामीणों को कहा गया है। प्रत्येक माह की 7 तारीख को आयोजित होने वाला रोजगार दिवस अवसर होता है कि जब एक साथ सभी ग्रामीणों के बीच विभिन्न विषयों को लेकर पहुंचते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि नवा तरिया, अमृत सरोवर, आजीविका डबरी, सामुदायिक डबरी, तालाबों का गहरीकरण, नए तालाबों का निर्माण, सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट, ग्रे वॉटर मैनेजमेंट जैसे कार्य चल रहे हैं। इन कार्यो से ग्रामीणों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्राम पंचायतो में लगाए गए क्यूआर कोड को मोबाइल फोन से स्कैन करने की जानकारी दी गई। बताया गया की क्यूआर कोड स्कैन करते ही विगत 3 वर्षो में ग्राम पंचायत में हुए पूरे निर्माण कार्यो की जानकारी ग्रामीणों अपने मोबाइल फोन में प्राप्त होगा।

सभी ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत है मांग के आधार पर कार्य प्रारंभ किया जा रहे हैं जिससे कि ग्रामीणों को रोजगार के लिए भटकने की जरूरत ना पड़े। प्रतिदिन औसत 82000 से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है। प्रतिदिन 261 रुपए का मजदूरी भुगतान ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है और आजीविका के नए कार्यो से ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

रानाटोला में आयोजित हुआ जन समस्या निवारण शिविर, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत रही थीम

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनपद पंचायत मोहला के ग्राम पंचायत रानाटोला में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की विशेष थीम पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत रही। ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाले सुशासन तिहार के अंतर्गत यह अंतिम क्लस्टर स्तरीय शिविर था, जिसमें रानाटोला, घावड़ेटोला, मरारटोला, तेलीटोला, आलकन्हार, चापाटोला, देवरसूर, रेगाकठेरा, कोर्रामटोला एवं पांडरवानी सहित कुल 10 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने स्टॉल लगाए गए, जहां विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री वितरण किया गया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जन समस्या निवारण शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं एवं मांगों को सीधे सुनकर उनका त्वरित समाधान किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत केवल एक थीम नहीं बल्कि विकसित और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प है, जिसमें ग्रामीण अंचलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण स्तर पर आयोजित अंतिम शिविर को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को सुशासन तिहार पोर्टल में दर्ज कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। जिला स्तर की समस्याओं एवं मांगों का निराकरण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य स्तर से संबंधित प्रकरणों को उच्च कार्यालयों को प्रेषित किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है।

कलेक्टर ने कहा कि शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने ग्रामीणों से विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी लेकर अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। साथ ही जल संरक्षण एवं जल संचय को बढ़ावा देने के लिए कोरिया मॉडल, कुआं-तालाब निर्माण एवं जल संरचनाओं के विकास पर विशेष बल दिया। उन्होंने ग्रामीणों को स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों तथा विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनने की प्रेरणा दी। कलेक्टर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने तथा अपने गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने किसानों एवं आम नागरिकों से एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराने की अपील की ताकि उन्हें कृषि एवं शासन की योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके।

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर आयोजित अंतिम शिविर के सफल आयोजन पर सभी विभागों के अधिकारियों एवं कमर्चारियों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा ग्रामीण नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य लखन कलामे, जनपद सदस्य श्रीमती अनीता जायसवाल, श्रीमती सीता देवी कोमरे, श्रीमती इंद्रा कोमरे, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर जी.आर. मरकाम, अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य, जनप्रतिनिधि पुलकित खंडेलवाल, कमल तापड़िया, राजू डोंगरे, भावेश ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

धानमंत्री किसान सम्मान निधि से मजबूत हो रही खेती

देश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ी जीवनदायिनी साबित हो रही है। इसी योजना से लाभान्वित कबीरधाम जिले के ग्राम सोनझरी निवासी किसान श्री पोषलाल साहू ने बताया कि उन्हें वर्ष 2019 से अब तक योजना की 22 किस्तों का लाभ प्राप्त हो चुका है। उनके खाते में अब तक 44 हजार रुपए की राशि मिल चुकी है। समय-समय पर सीधे बैंक खाते में मिलने वाली सहायता राशि ने उनकी खेती-किसानी को नई मजबूती दी है। पोषलाल साहू बताते हैं कि पहले खेती के मौसम में खाद, बीज और अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था करने में कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली राशि जरूरत के समय सहारा बन रही है। वे इस राशि का उपयोग खेती की तैयारी, कृषि सामग्री की खरीद और अन्य आवश्यक खर्चों में करते हैं, जिससे खेती का काम समय पर शुरू हो जाता है। उन्होंने बताया कि खेती के दौरान छोटी-छोटी जरूरतों के लिए तत्काल धन की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में योजना के तहत सीधे खाते में आने वाली सहायता राशि आर्थिक दबाव कम करने में मदद करती है। इससे कृषि लागत का बेहतर प्रबंधन संभव हुआ है और खेती के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता राशि तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। हाल ही में योजना की 22वीं किस्त भी जारी की गई है। इस योजना की विशेषता यह है कि सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदशिर्ता सुनिश्चित होती है और किसानों को समय पर लाभ प्राप्त होता है।

एनएसयूआई ने दुर्ग विवि और साइंस कॉलेज में सौंपा ज्ञापन

प्रवेश प्रक्रिया, एबीसी आईडी और परीक्षा परिणाम से जुड़ी 5 सूत्रीय मांगें रखीं

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय और शासकीय साइंस कॉलेज दुर्ग में छात्र समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महासचिव आदित्य नारंग के निर्देश पर संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन के सामने पांच सूत्रीय मांगें रखीं।

विवि प्रशासन को सौंपी मांगें

एनएसयूआई ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल जल्द शुरू करने की मांग की। फॉर्म भरते समय एबीसी आईडी वेरिफिकेशन में आ रही समस्या का निवारण करने, हेल्पलाइन और गाइड करने के लिए व्यक्ति की नियुक्ति करने की बात कही। कैंपस में प्रवेश प्रक्रिया के लिए हेल्प डेस्क बनाने की मांग भी रखी गई। विभिन्न सेमेस्टर के परिणाम जल्द घोषित करने और असंतोषजनक परिणाम की पुनः जांच कराने की मांग की गई।

साइंस कॉलेज में भी उठे मुद्दे

साइंस कॉलेज दुर्ग में प्राचार्य को सौंपे ज्ञापन में महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल में सुधार, अइउ आईडी वेरिफिकेशन की समस्या के निवारण, हेल्पलाइन व गाइड नियुक्त करने की मांग की गई। कैंपस में हेल्प डेस्क स्थापित करने, ढत्रकृऌअ सेमेस्टर परिणाम से असंतुष्ट छात्रों की समस्या हल करने की बात कही। पानी और पार्किंग की सुविधा सुचारू करने की मांग भी शामिल रही। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन ने मांगों का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया।

ज्ञापन सौंपने वालों में एनएसयूआई के छात्र नेता युवा चंद्राकर, मयंक देशमुख, मृदुल सिंह, अभय देशलहरा, दिशा भारती, रिया दत्ता, अंजलि साव सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

वृद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लायनेस क्लब भिलाई मेन ने रामालया मंदिर में व्हीलचेयर दान की

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

लायनेस क्लब भिलाई मेन द्वारा CG1 स्वर्णिम 2026 के तहत रामालया मंदिर, हुडको में सेवा गतिविधि आयोजित की गई। क्लब ने जरूरतमंद एवं वृद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक व्हीलचेयर दान की।

पुत्र के जन्मदिन पर समर्पित सेवा

क्लब अध्यक्ष लायनेस रेवेका बेदी ने यह सेवा कार्य अपने पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर समर्पित किया। व्हीलचेयर का उद्देश्य मंदिर आने-जाने में असमर्थ वृद्ध एवं असहाय श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन का अवसर देना है।

सदस्यगण रहीं उपस्थित

कार्यक्रम में कैबिनेट सचिव लायनेस विभा भुटानी, लायनेस सीमा यादव, लायनेस मीरा शर्मा एवं लायनेस शेना शेखर मौजूद रहीं। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मास्टर मनदीप बेदी भी उपस्थित रहे।

लायनेस क्लब भिलाई मेन ने बताया कि यह पहल समाज में सहयोग, करुणा एवं सेवा भावना को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।

दुष्कर्म : पीड़िता का दादा गिरफ्तार, पैसे लेकर मामला दबाने का आरोप

दो बिचौलियों सहित तीन आरोपी जेल भेजे, 1 लाख नगद बरामद

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-सिलयारी

चौकी सिलयारी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि पीड़िता के दादा ने ही 1 लाख 30 हजार रुपये लेकर मामले को दबाने का प्रयास किया था। पुलिस ने पीड़िता के दादा समेत दो बिचौलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी दादा से 1 लाख रुपये नगद जब्त किए गए हैं।

18 अप्रैल को दर्ज हुआ था केस

दिनांक 18.04.2026 को दर्ज दुष्कर्म के प्रकरण में पुलिस ने नए सिरे से विवेचना की। दो दुष्कर्म आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जांच आगे बढ़ाने पर पुलिस को अहम साक्ष्य मिले।

पैसे लेकर दबाया मामला, वीडियो भी बना

जांच में पता चला कि पीड़िता के दादा ने आरोपी ईश्वर घृतलहरे के परिजनों से दुष्कर्म की घटना छिपाने के एवज में 1 लाख 30 हजार रुपये नगद लिए थे। इस लेनदेन का वीडियो भी बनाया गया था। दादा ने दूसरे आरोपी को फोन कर धमकी भी दी थी।

शासकीय सहायता के लालच में बदला बयान

जांच में यह भी सामने आया कि पीड़िता के दादा ने पहले अपने कथनों में नातिन के साथ किसी घटना से इनकार किया था। बाद में लोगों से सुनने के बाद कि दुष्कर्म के मामले में शासन से 4 लाख रुपये की सहायता मिल सकती है, उन्होंने पुनः जांच के लिए आवेदन दिया था।

तीन आरोपी गिरफ्तार

गंभीर अपराध को धन लेकर दबाने के आरोप में पुलिस ने पीड़िता के दादा, सीताराम मेडिकल स्टोर के संचालक चन्द्रशेखर यदु तथा टुकेन्द्र वर्मा को 09.06.2026 को गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

जिला अस्पताल दुर्ग की अव्यवस्था पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को सौंपा गया ज्ञापन, जांच की मांग

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रदेश कांग्रेस सचिव अय्यूब खान ने नया रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया से मुलाकात कर जिला अस्पताल दुर्ग की अनियमितताओं पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की।

ब्लड उपलब्ध होने पर भी युवती की मौत

अय्यूब खान ने बताया कि 01 जून 2026 को जिला अस्पताल दुर्ग में ब्लड उपलब्ध होने के बाद भी युवती दीपिका यादव की मौत हो गई। रक्त न देना प्रशासन की घोर लापरवाही और कालाबाजारी की ओर इशारा करता है। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

न्यूरोसर्जन नहीं, ट्रामा सेंटर में डॉक्टर गायब

जिला अस्पताल में न्यूरोसर्जन की पदस्थापना नहीं है। सिर की चोट वाले मरीजों को रायपुर रेफर किया जाता है जिससे कई मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ट्रामा सेंटर में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। आपातकाल में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता।

बिना जांच रेफर

अय्यूब खान ने कहा कि मरीजों को बिना प्राथमिक जांच के ही रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन बंद है। गंभीर मरीजों को निजी सेंटर में महंगी जांच करानी पड़ती है। उन्होंने सीटी स्कैन 24 घंटे चालू करने और रेफर से पहले प्राथमिक उपचार अनिवार्य करने की मांग की।

मर्चुरी फ्रिज बंद, नसबंदी में दो मौतें

ज्ञापन में कहा गया कि अस्पताल का मर्चुरी फ्रिज कई दिनों से बंद है। इससे शव रखने में परिजनों को परेशानी हो रही है। कुछ दिन पहले नसबंदी शिविर में लापरवाही से 2 महिलाओं की मौत हुई। दोषी डॉक्टरों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई।

सरायपाली : फाइनेंस कंपनी के 22.66 लाख गबन मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / महासमुंद

भारत फाइनेंस इंक्लूजन कंपनी सरायपाली ब्रांच में 22.66 लाख रुपये के गबन मामले में पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 341/2025 धारा 316(5), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है। प्रकरण में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट : क्षेत्रीय प्रबंधक हेमेन्द्र राजाराम जनबन्धु ने 22 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि

कंपनी के ब्रांच मैनेजर शुभम पाणीग्राही, फील्ड मैनेजर दीपक कुमार, फील्ड मैनेजर रोहन प्रधान तथा ब्रांच क्रेडिट मैनेजर प्रमोद महंत ने मिलकर कुल 22,66,645 रुपये का गबन किया।

किसने कितना किया गबन : शुभम पाणीग्राही ने 13 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 तक 16 हितग्राहियों से 5,35,869 रुपये वसूली कर बैंक में जमा नहीं किए। दीपक कुमार ने 13 जून 2023 से 08 नवंबर 2023 तक 16 हितग्राहियों से 1,58,961 रुपये, रोहन प्रधान ने 27 फरवरी 2022 से 24 नवंबर 2023 तक 55 हितग्राहियों से 5,54,583 रुपये तथा प्रमोद महंत ने 04 जनवरी 2024 से 13 अगस्त 2024 तक 16 हितग्राहियों से 10,17,232 रुपये का गबन किया।

तकनीकी जांच के बाद पकड़े गए आरोपी : प्रकरण दर्ज होने के बाद तीनों आरोपी फरार थे। सीडीआर विश्लेषण, तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 08 जून 2026 को आरोपी रोहन प्रधान, उम्र 24 वर्ष, निवासी झगरेनडीह थाना पिथौरा एवं प्रमोद महंत, उम्र 34 वर्ष, निवासी पुसलदा थाना छाल जिला रायगढ़ को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पूर्व में एक आरोपी हो चुका गिरफ्तार : इस मामले में 14 मार्च 2026 को शुभम पाणीग्राही पिता देवेन्द्र पाणीग्रही, उम्र 30 वर्ष, निवासी सिंघोड़ा थाना सिंघोड़ा जिला महासमुंद को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड इंडसइंड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति से बैंकिंग व्यवसाय करती है।

मोबाइल झपटमारी के दो मामले सुलझे, 8 आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

चौकी अंजोरा पुलिस ने मोबाइल झपटमारी और लूट के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों और 3 विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, धारदार हथियार और अन्य सामग्री सहित करीब 1.40 लाख रुपये का मशरूका बरामद हुआ है।

पहला मामला: 06 जून 2026 की रात महमरा शिवनाथ नदी एनीकेट पर प्रार्थी के साथी के हाथ से मोबाइल झपट लिया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने एक आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा। लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया गया। चोरी का मोबाइल खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।

दूसरा मामला: 17 अप्रैल 2026 की रात रसमड़ा हाईवे रोड पर रॉयल ग्रीन होटल के सामने राहगीर को रास्ता पूछने के बहाने रोककर उसकी शर्ट की जेब से दो मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड झपट लिए गए। आरोपियों ने प्रार्थी को धक्का देकर फरार हो गए। तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी और दो विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर चोरी का मोबाइल खरीदने वाले को भी पकड़ा गया।

गिरफ्तार आरोपियों में यश कुमार साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी शक्ति नगर दुर्ग, प्रशिक्षित सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी दीपक नगर दुर्ग, संदीप कौशल, उम्र 19 वर्ष, निवासी सिकोला भाटा दुर्ग, ध्रुव वैश्य, उम्र 22 वर्ष, निवासी मदर टेरेसा नगर सुपेला दुर्ग और तीन विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100